



3 जम्मू-कश्मीर के खिलाड़ियों की अपेक्षा पर जताया विरोध

5 कुछ लोगों को हमेशा होती है शिकायत करने की आदत: गंभीर

8 फ्रेंचबीन (फ्रांसबीन) की खेती

न्यूनतम 10

मौसम अधिकतम 24 जम्मू



जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

देहात सन्देश



देश की सोच बदलने के कारण आज का भारत बड़े लक्ष्य हासिल करके दिखा रहा है : मोदी

नई दिल्ली, 06 मार्च। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में पिछले एक दशक में किए गए सुधारों कार्यों की बदौलत जनमानस में जागे आत्मविश्वास का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की सोच बदलने के कारण आज का भारत बड़े लक्ष्य हासिल करके दिखा रहा है। प्रधानमंत्री गुरुवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में रिपब्लिक प्लेनरी समिट को संबोधित कर रहे थे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया कह रही है कि यह भारत की सदी है। भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों ने वैश्विक स्तर पर नई आकांक्षाओं और उम्मीदों को जगाया है। एक समय ऐसा था जब यह कहावत प्रचलित थी कि 'वो तो डूबेगा, हमें भी ले डूबेगा', लेकिन अब भारत वैश्विक विकास को आगे बढ़ाने वाली एक प्रेरक शक्ति के रूप में उभरा है।



उन्होंने कहा कि आज का भारत बड़ा सोचता है और बड़े लक्ष्य तय करता है और आज का भारत बड़े नतीजे लाकर दिखा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज देश की सोच बदल गई है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश के लोगों की प्रेरणा को कुचल दिया था। इसलिए देश के लोगों ने उम्मीद लगानी भी छोड़ दी थी। आज देखिए, हालात और सोच कितनी तेजी से बदल गई है। अब लोग जानते हैं कि कौन काम कर

सकता है, कौन नतीजे ला सकता है। आज सदन में विपक्ष भी यही भाषण करता है कि मोदी जी ये क्यों नहीं कर रहे हो। इसका मतलब है कि उनको भी लगता है कि यही करेगा। प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को लेकर कहा कि देश में नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है। पहले 100 से अधिक जिले इस समस्या से बुरी तरह प्रभावित थे। लेकिन आज यह संख्या घटकर मात्र दो दर्जन रह गई है। यह महत्वपूर्ण प्रगति राष्ट्र प्रथम दृष्टिकोण को प्राथमिकता देने से हासिल हुई है। इन क्षेत्रों में हमने जमीनी स्तर पर शासन देने पर ध्यान केंद्रित किया। लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हजारों किलोमीटर सड़कें बनाई गईं और स्कूल तथा अस्पताल बनाए गए। इन प्रयासों का असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि निर्णायक कार्रवाई के कारण जहां वन

क्षेत्रों से नक्सलवाद का धीरे-धीरे ख़ात्मा हो रहा है, वहीं इसने शहरी क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया है, जो एक नई चुनौती पेश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 250 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स देश में बन गए हैं, ये हमारे देश के युवाओं के कमाल हैं। भारत में गांव के घरों के प्रॉपर्टी राइट्स देने के लिए हमने रवामित्व स्क्रीम शुरू की। इसके लिए हम गांव-गांव में ड्रोन से सर्वे करा रहे हैं और गांव के एक-एक घर की मैपिंग करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में, मुझे लगा कि मुझे एक लाख युवाओं को राजनीति में लाना चाहिए, और वे अपने परिवारों से पहली बार आने वाले होने चाहिए। इस तरह का आयोजन उस उद्देश्य के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट-2024-25 पेश की

‘जम्मू-कश्मीर में मंत्रिपरिषद में कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा में कुल सदस्यों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए’

जम्मू 06 मार्च। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वर्ष 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति सदन के पटल पर रखी। जम्मू-कश्मीर सरकार ने गुरुवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में मंत्रिपरिषद में कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा में कुल सदस्यों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद गनी लोन के प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री हैं ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 के अनुसार मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 10



प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों के पास मौजूद विभागों के नामों के बारे में पूछे गए प्रश्न पर सरकार ने पांच कैबिनेट मंत्रियों के पास मौजूद विभागों के नाम निर्दिष्ट किए हैं लेकिन मुख्यमंत्री के पास मौजूद

विभागों के नामों का उल्लेख नहीं किया है। लिखित उत्तर में सरकार ने कहा कि किसी भी माननीय मंत्री को आवंटित नहीं किए गए विभाग माननीय मुख्यमंत्री के पास हैं। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को घोषणा की

कि कुपवाड़ा जिले में बुगस घाटी को एक अनोखे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है और इस क्षेत्र के लिए कुल 72 लाख रुपये के विकास कार्य प्रस्तावित हैं। प्रश्नकाल के दौरान जम्मू-कश्मीर विधानसभा सदस्य शेख खुशीद के एक सवाल का जवाब देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि 2024-25 के लिए योजना के लिए स्वीकृत आवंटन 30 लाख रुपये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगस को एक अनोखे गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने पूंजीगत बजट 2024-25 के तहत 72 लाख रुपये की राशि के विकास कार्यों का प्रस्ताव दिया है।

स्लैब के नीचे आने से व्यक्ति की मौत श्रीनगर, 6 मार्च।

त्राल में गुरुवार को स्लैब गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब्दुल रहमान हजाम का पुत्र खुशीद अहमद हजाम गिरते हुए स्लैब के नीचे आ गया जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। इसकी पुष्टि करते हुए एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने आगे की जांच के लिए घटना का संज्ञान लिया है और जांच शुरू हो गई है।

ओवर ग्राउंड वर्कर पर पीएसए के तहत मामला दर्ज

कटुआ 06 मार्च। एसएसपी कटुआ शोभित सक्सेना की समग्र देखरेख में कटुआ पुलिस ने विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल 01 हाईकोर अपराधी/ओवर ग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार कर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978 (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया।

जनकारी के अनुसार एसडीपीओ बिलावर और एसएसओ पुलिस स्टेशन बिलावर की देखरेख में प्रभारी पुलिस पोस्ट रामकोट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक ओवर ग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया जिसका नाम भुट्ट पुत्र गामी निवासी धनोपरोल तहसील बिलावर जिला कटुआ है जो पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न अवैध गतिविधियों में शामिल है।

जिले के भीतर अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आरोपी व्यक्ति के खिलाफ डेजियर तैयार किया गया और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978 के तहत उसकी हिरासत के लिए जिला मजिस्ट्रेट कटुआ को भेजा गया। तदनुसार जिला मजिस्ट्रेट कटुआ ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978 के तहत आरोपी व्यक्ति के खिलाफ नजरबंदी वारंट जारी किया। तदनुसार, वारंट आज निष्पादित किया गया है और उनकी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उन्हें जिला जेल उधमपुर में रखा गया है।

पुलिस ने अलूसा बांदीपोरा में पांच फरार आतंकवादियों की संपत्तियां जब्त कीं

जम्मू, 6 मार्च। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के अलूसा इलाके में पांच फरार आतंकवादियों की संपत्तियां जब्त कीं। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जब्त की गई 18 कनाल की जमीन पांच फरार आतंकवादियों की है जिनमें फारुक अहमद गनी, मोहम्मद अब्दुल्ला मलिक, मोहम्मद युनुस गुज्जर तुरक, सरफराज गुज्जर तुर्क और राशिद गुज्जर शामिल हैं। ये सभी अलूसा बांदीपोरा के निवासी हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस कश्मीर में आतंकवाद पर लगातार कार्रवाई कर रही है और इससे समर्थक नेटवर्क को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य में जिले के अन्य हिस्सों में फरार आतंकवादियों की और संपत्तियां जब्त की जाएंगी।

जम्मू-कश्मीर मसले का एकमात्र हल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले हिस्से की वापसी : जयशंकर

लंदन, 06 मार्च। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर मसले का एकमात्र बाकी हल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले हिस्से की वापसी है।

डॉ. जयशंकर ने कल शाम यहां वैथम हॉल में संवाद कार्यक्रम में एक पाकिस्तानी पत्रकार के जम्मू-कश्मीर के मसले के समाधान के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा, हमने इसमें से अधिकांश को हल करने के लिए अच्छा काम किया है। अनुच्छेद 370 को हटाना, विकास और समृद्धि को बहाल करना, चुनाव आयोजित करना जिसमें अभूतपूर्व मतदान दर्ज किया गया है।

विदेश मंत्री ने कहा, हम जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, वह कश्मीर के चोरी हुए हिस्से की



वापसी है, जो अवैध पाकिस्तानी कब्जे में है। जब ऐसा किया जाएगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कश्मीर मसला हल हो जाएगा।

पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा था कि अमेरिका में

जम्मू-कश्मीर सरकार ने कहा कि 269 निर्माणों को विचलन के लिए नोटिस जारी किए गए

जम्मू, 06 मार्च। जम्मू-कश्मीर सरकार ने गुरुवार को कहा कि पहलगांव विकास प्राधिकरण (पीडीए) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में निर्माण में विचलन के लिए 269 नोटिस जारी किए गए हैं। पहलगांव में अवैध और अनधिकृत निर्माणों की कुल संख्या के बारे में विधायक पुलवामा वहीद-उर-रहमान पारा के प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो पर्यटन विभाग के मंत्री भी हैं ने कहा कि पीडीए ने हाल ही में प्राधिकरण के बीओसीए द्वारा जारी अनुमतियों के

अनुसार 269 विचलनों को नोटिस जारी किए हैं। मंत्री ने कहा कि हालांकि इनमें से अधिकांश में पीएमवाई और स्थानीय लोगों के आवासीय घर शामिल हैं जो संबंधित प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मंत्री ने कहा कि पहलगांव विकास प्राधिकरण नोडल कार्यालय है जो अधिसूचित क्षेत्रों पीडीए के अधिकार क्षेत्र में होने वाले विचलन अवैध और अनधिकृत निर्माणों की जांच करता है और जब भी आवश्यकता होती है ध्वस्तीकरण अभियान चलाता है।

राजस्व विभाग ने जनता की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया: सकीना इत्तू

जम्मू, 6 मार्च। स्वास्थ्य और विकसिता शिक्षा, समाज कल्याण और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने कहा कि सरकार ने जनता की आसानी के लिए विभिन्न राजस्व सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। मंत्री ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से विधायक सुरिंदर कुमार द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही। मंत्री ने सदन को बताया कि राजस्व विभाग ने आवेदक के लिए प्रक्रिया में आसानी सुनिश्चित करने के लिए सीएल्यू के आवेदन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल रातमअमदमदमदबजणपर विकसित किया है। उन्होंने कहा कि

इस पोर्टल के साथ आवेदक को ऐसी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री ने धारा 133 ए, प्रोविजो 2 कृषि भूमि की हवाला दिया। उन्होंने कहा ऋबशर्त कि किसी भी कृषि भूमि का धारक संबंधित तहसीलदार को सूचित करने पर आवासीय घर का निर्माण कर सकता है या कृषि भवन, अनाज भंडारण, कृषि उपज का प्राथमिक प्रसंस्करण, कृषि या टैंक बना सकता है या आवासीय उद्देश्य या कृषि सुधार के लिए कोई अन्य सुधार कर सकता है, हालांकि, ऐसे भवन या सुधार का क्षेत्र कुल मिलाकर चार सौ वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा।

उपराज्यपाल ने दर्शनी देवड़ी, बाणगंगा और अर्धकुंवारी में तीर्थयात्रियों की सुविधाओं का किया उद्घाटन

जम्मू, 06 मार्च। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को राजभवन में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) की 74वीं बैठक की अध्यक्षता की। बोर्ड की बैठक में पिछले निर्णयों की व्यापक समीक्षा की गई और तीर्थयात्रियों की सेवाओं को बढ़ाने के लिए कई नए निर्णय लिए गए। इसके बाद उपराज्यपाल ने दर्शनी ड्योद्री, बाणगंगा में कतार परिसर और अर्धकुंवारी में होलिडिंग एरिया सहित कई तीर्थयात्री-केंद्रित सुविधाओं का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बोर्ड



की बैठक में नई और चल रही परियोजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जैसे भवन में एक्विजिट ट्रेक का निर्माण और मनोकामना क्षेत्र का पुनर्निर्माण (भवन क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान का एक हिस्सा), कटरा के हट्ट गांव में श्रीशिव खोरी श्राइन

बोर्ड के सहयोग से हेलीपैड का विकास, भवन में नया वैष्णवी भवन, खेल स्टेडियम के पास कॉटेज, कटरा, सांडीछत से भवन तक यात्रा ट्रेक का चौड़ीकरण और ककरयाल में बोर्ड के मेडिकल कॉलेज का संचालन।

डूरू-वैरिनाग के लिए 3 टोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्वीकृत

जम्मू, 06 मार्च। समाज कल्याण मंत्री सकीना इत्तू ने आज सदन को सूचित किया कि नगरपालिका समिति डूरू/वैरिनाग स्रोत पर कचरे को अलग करने के लिए सभी घरों में दोनों घरेलू कूड़ेदान वितरित करती है, साथ ही अंतर्नाग जिले के दोनों शहरों में कचरे के अलग-अलग संग्रह के लिए वाणिज्यिक क्षेत्रों में जुड़वा कूड़ेदान स्थापित करती है। मंत्री ने विधानसभा में जी. ए. मीर द्वारा उठाए गए एक सवाल पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से जवाब देते हुए यह बात कही। मंत्री ने कहा कि घरों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से कचरा एकत्र करने के लिए, 08 हॉपर नियमित रूप से तैनात किए जाते हैं और कचरे को बाद में वैरिनाग में सामग्री रिकवरी सुविधा संयंत्र में ले जाया जाता है।

कलोरेन भीनी नाला पुल के लिए 583.78 लाख रुपये की डीपीआर बनाई गई: उप मुख्यमंत्री



जम्मू 06 मार्च। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने विधायक डॉ. रामेश्वर सिंह के सवाल का जवाब देते हुए सदन को बताया कि बनी में कालोरन, गंगला डल रोड पर भीनी नाला पर पुल के निर्माण के लिए 583.78 लाख रुपये की एक व्यापक डीपीआर तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि 583.78 लाख रुपये की लागत से 700 मीटर

एप्रोच रोड के साथ 75 मीटर स्पान पुल के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार किया गया है, जो संसाधनों की उपलब्धता के अधीन अगले वित्तीय वर्ष के दौरान मंजूरी देने वाले अधिकारियों के सक्रिय विचारार्थीन है। उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस संबंध में शिकायत एलजी मुलाकात के वेब पोर्टल पर दर्ज की गई है।

4.26 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का जैविक उपचार किया गया, 33 पृथकरण मशीनें चालू हैं : सरकार



जम्मू, 6 मार्च। जम्मू-कश्मीर सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसने केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न लैंडफिल साइटों पर डंप किए गए 4.26 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का सफलतापूर्वक जैविक उपचार

किया है। विधानसभा में विधायक मीर मोहम्मद फैयाज के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो आवास और शहरी विकास विभाग के प्रभारी हैं ने बताया कि वर्तमान में प्रभावी

अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जम्मू-कश्मीर में 33 मैकेनिकल सेग्रीगेशन मशीनें चालू हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि उचित खरीद प्रक्रिया का पालन करते हुए स्वीकृत योजना के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत अतिरिक्त मशीनें खरीदी जा रही हैं। अब तक केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न जिलों में खुले लैंडफिल साइटों पर डंप किए गए 4.26 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियम 2016 के अनुसार सफलतापूर्वक जैविक उपचार किया गया है।

एक महीने के भीतर एक व्यापक होम स्टे नीति तैयार करें: मुख्य सचिव

जम्मू, 06 मार्च। मुख्य सचिव अटल डल्लू ने पर्यटन विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जेएडके बैंक के एमडी और अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया, ताकि जम्मू-कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र के समग्र प्रचार के लिए होमस्टे को मजबूत करने के लिए विभाग द्वारा उठाए गए कदमों, नीतिगत अपडेट और सुधार की गुंजाइश का मूल्यांकन किया जा सके। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने विभाग को यूटी के जिलों में होमस्टे के विकास के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद अगले एक महीने में इसे तैयार करने का आह्वान



किया। उन्होंने वित्तीय संस्थानों द्वारा एक नया ऋण उत्पाद विकसित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया, जिसमें यहां होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए की जा सकने वाली हर गतिविधि शामिल होगी। उन्होंने होमस्टे में परिवर्तित किए जा सकने वाले कमरों की संख्या बढ़ाने के विकल्प पर

विचार करने की सलाह दी। साथ ही, यहां होमस्टे के निर्माण और उन्नयन के लिए वित्त की मात्रा भी सुनिश्चित करने की सलाह दी। अटल डल्लू ने इस बात पर जोर दिया कि इस पर्यटन अभ्यास से जुड़े लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस योजना का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए।

छुट्टियों में लें गोआ का मजा

भारत के पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में गोवा का उल्लेख मिलता है। इसे पहले गोपराष्ट्र, गोपकपुरी, गोपकपट्टन, गोअंचल, गोवे, गोवापुरी, गोपकापाटन, गोमंत, चंद्रपुर और चंदौर नाम से जाना जाता था। परशुराम ने बाणों की वर्षा से इसे पीछे धकेल दिया था, इसी कारण इसे वाणस्थली भी कहा जाता है। जिस स्थान का नाम पुर्तगाल के यात्रियों ने गोवा रखा, वह आज का छोटा-सा समुद्र तटीय शहर गोअ-वेल्हा है। बाद में समूचे द्वीप क्षेत्र को गोआ या गोवा कहा जाने लगा। पुर्तगालियों ने यहां ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार किया। गोवा लगभग 500 वर्ष तक पुर्तगालियों के अधीन रहा। यहां की मातृ भाषा कोंकण और मराठी है। 1000 साल पहले कहा जाता है कि गोआ कोंकण काशी के नाम से जाना जाता था। हालांकि पुर्तगाली लोगों ने यहां के इतिहास और मूल संस्कृति का नामोनिशान मिटाकर धर्मांतरण का ही काम किया हो, ऐसा नहीं, उन्होंने यहां की प्राकृतिक और धन संपदा को लूटकर पुर्तगाल में भेज दिया।

भारतीय राज्य गोवा के तट विश्व प्रसिद्ध हैं। दुनिया भर से यहां लोग छुट्टियां मनाने आते हैं। गोवा चारों ओर समुद्र से घिरा है। यहां पहुंचने के लिए मुख्यतः दो मार्ग हैं- महाराष्ट्र के मुंबई से गोवा और कर्नाटक के बेलगाम से गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है।

प्रदेश के सुनहरे लम्बे समुद्र तट, आकर्षक चर्च, मंदिर, पुणे किले और कलात्मक भग्नावशेषों ने पर्यटन को गोवा का प्रमुख उद्योग बना दिया है।

जहां, यहां संगीत, नाच-गाना, ड्रम और गिटार की धुनें शांत, स्वच्छ व मनोरंजक वातावरण प्रस्तुत करती हैं, वहीं यहां का समुद्री भोजन दुनिया भर में प्रसिद्ध है। भरपूर मौज मस्ती और मनोरंजन के लिए गोवा एक आदर्श स्थान है।

संपूर्ण गोवा में इतने अधिक समुद्र तट हैं कि पर्यटकों को गोवा के सभी तटों को देखने में एक महीने से भी अधिक वक्त लग जाएगा। गोवा के इन समुद्र तटों पर, आप समुद्र की लहरों पर वॉटर सर्फिंग, पैरासेलिंग, वॉटर स्किइंग, स्कूबा डाइविंग, वॉटर स्क्वटर आदि का लुफ्त उठा सकते हैं।

पणजी, मडगांव, वास्को, मापुसा तथा पोंडा राज्य के प्रमुख शहर हैं। पणजी गोवा राज्य की राजधानी है, जो मांडवी नदी के तट पर स्थित है। यहां मांडवी नदी के ऊपर बना ब्रिज देखने लायक है।

पणजी में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च और मूर्ति मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर सहित कई प्राचीन मंदिर और चर्च हैं। यहां का पुराना शहर देखने लायक है। यहां अंग्रेजों के जमाने की जेल है, जहां स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों को रखा जाता था। यहां नदी और समुद्र का संगम भी एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है।

हम सभी को छुट्टियों का बहाना चाहिए। छुट्टियों का यदि सदुपयोग हो जाए तो उसका पूरा-पूरा मजा लिया जा सकता है। गोआ एक ऐसा स्थान है, जहां आप जिंदगी का भरपूर मजा ले सकते हैं।

यहां के लुभावने समुद्र तट व फ्रेंक लाइफ स्टाइल आपमें एक नई ऊर्जा का संचार कर देगी। यदि आप उन्मुक्तता पसंद करते हैं और अपने जीवनसाथी के साथ अंतरंग पल गुजारना चाहते हैं तो गोआ आपके लिए बेहतर पर्यटन स्थल सिद्ध होगा।

लुभावने समुद्र तट

गोआ भारत का एक ऐसा राज्य है जहां अनगिनत समुद्र तट हैं, जहां की स्वच्छंद व उन्मुक्त लाइफ स्टाइल पर्यटकों को गोआ की ओर खींच लाती है। गोआ में इतने अधिक बीच हैं कि पर्यटक को गोआ के सभी बीचों को देखने में एक महीने से भी अधिक का वक्त लग जाएगा।

विदेशी सैलानियों की बहुतायत व लुभावने समुद्र तट का मस्त नजारा भारतीय पर्यटकों को भी सहसा गोआ आने को आमंत्रित करता है।

नवविवाहितों के हनीमून के लिए भी गोआ एक बढ़िया स्थान है।

गोआ के कुछ प्रसिद्ध बीच दोला पाउला, कैलेंगुट, अंजुना, आरामबोल, कोलवा, मोरामार, वागाटोर, अगोडा आदि हैं, जिनमें होकर मांडवी, चापोरा, जुआरी, साल, तालपोना और तीराकोल नामक छह नदियां बहती हैं।

अंजुना बीच

यह डबोलिन एयरपोर्ट से 57 किमी दूर स्थित है। यह गोआ के बड़े समुद्र तट में शुमार है। अंजुना बीच उत्तर, दक्षिण और मध्य तीन भागों में विभाजित है। इसके उत्तरी भाग में कई सारे बड़े, रेस्टोरेंट व होटल हैं। इस बीच पर एक बहुत बड़ा साप्ताहिक बाजार भी लगता है।

कैलेंगुट बीच

यह गोआ के समुद्र तट में सबसे खूबसूरत बीच है। डबोलिन एयरपोर्ट से इसकी दूरी 48 किमी है। यह गोआ पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। यहां के तट नाइट डिस्को, रेस्टोरेंट व मार्केट पर्यटकों की पहली पसंद है। इस खूबसूरत बीच के आसपास बागा और कोडोलिन दो अन्य समुद्र तट हैं। यह बीच तैराकी के लिए बहुत अच्छी जगह है। वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी गोआ बहुत प्रसिद्ध है। गोआ के इन समुद्र तटों पर आप समुद्र की लहरों पर वाटर सर्फिंग, पैरासेलिंग, वाटर स्किइंग, स्कूबा डाइविंग, वाटर स्क्वटर आदि का लुफ्त उठा सकते हैं।

मानसून में गोआ की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। हरियाली की चादर ओढ़ने से यहां के समुद्रतटीय इलाके व सड़के और खूबसूरत हो जाती है और ऐसे में गोआ की सड़कों पर अपने हमसफर के साथ लॉग ड्राइंग का मजा ही कुछ और होता है। आपको यहां बाइक आसानी से किराए पर मिल जाएगा, जिसकी सवारी करके आप गोआ के हसीन नजारों का आनंद उठा सकते हैं।

गोआ के प्रमुख शहर

पणजी

पणजी गोआ की राजधानी व एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। यहां की संकरी गलियां और उनमें स्थित सुंदर चर्च पणजी को एक अलग ही खूबसूरती प्रदान करते हैं। यहां का चर्च ऑफ अवर लेडी डमेक्विलेट, लागो दा इग्रजा, गोआ स्टेट म्यूजियम, जामा मस्जिद, दूधसागर फॉल, महालक्ष्मी मंदिर और मास्ती मंदिर पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण का केंद्र है।

मपुसा

यह गोआ का एक प्रमुख तीसरा बड़ा शहर है। शुक्रवार को लगने वाला यहां का साप्ताहिक बाजार पर्यटकों के लिए खरीददारी का अच्छा स्थान है। यहां का पुराना हनुमान मंदिर, द चर्च ऑफ अवर लेडी मिरैकल, लार्ड बोधेश्वर टेंपल, टोडा आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं।

मडगाँव

यह दक्षिणी गोआ का प्रमुख नगर है। यह गोआ का दूसरा बड़ा शहर तथा व्यावसायिक केंद्र है। यहां के मार्केट बहुत प्रसिद्ध है। यदि आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो मडगाँव आपके लिए एक अच्छा स्थान



है। यहां के पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र चर्च ऑफ होली स्प्रिट, हाऊस ऑफ सेवन गेबेल्स, कोल्वा बीच, एनसेस्ट्रल गोआ आदि हैं।

गोआ के ऐतिहासिक चर्च व खूबसूरत मंदिर

गोआ के ऐतिहासिक चर्च व खूबसूरत मंदिर भी पर्यटकों को गोआ में छुट्टियां बिताने को आमंत्रित करते हैं। गोआ के ऐतिहासिक चर्चों में सेंट फ्रांसिस, ऑफ असीसी, होली स्प्रिट, पिलर सेमिनरी, सालीगाँव, रकोल आदि चर्च हैं। इसके अतिरिक्त सेंट काजरन चर्च, सेंट आगस्टोन टॉवर, ननरी ऑफ सेंट मोनिका तथा सेंट ऐरक्स चर्च भी प्रसिद्ध है। गोआ के प्रसिद्ध मंदिरों में कामाक्षी, सप्तकैटेश्वर, श्री शांतादुर्गा, महालसा नारायणी, परनेम का भगवती मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर आदि हैं।

गोआ के अभ्यारण

गोआ के कई संग्रहालय व अभ्यारण हैं। बोंडला अभ्यारण, कावल वन्य प्राणी अभ्यारण, कोटिजाओ वन्य प्राणी अभ्यारण

आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा गोआ का अगुडा किला भी प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है।

कब जाएं

गोआ जाने का सबसे बेहतरीन समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है। इस मौसम में यहां बहुतायत में पर्यटक आते हैं। जून से सितंबर तक यहां बहुत अधिक वर्षा होती है इसलिए इस मौसम में यहां पर्यटक कम ही आते हैं। ईसाइयों की बहुलता के कारण क्रिसमस के समय गोआ में बहुत सारे सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, जिनका आनंद लेने के लिए पर्यटक इस समय विशेष तौर पर गोआ आते हैं।

कैसे पहुंचे

गोआ का निकटतम हवाईअड्ड डबोलिन हवाई अड्डा है, जो गोआ से लगभग 29 किमी दूर है। गोआ के लिए दिल्ली मुंबई, बंगलुरु और चेन्नई से सीधी विमान सेवा उपलब्ध है। गोआ कोंकण रेलवे से जुड़ा है अतः ट्रेन से भी आप आसानी से गोआ पहुंच सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा भी गोआ का सीधा संबंध मुंबई बंगलुरु पुणे आदि शहरों से है।



संपादकीय

यातायात नियमों का उल्लंघन, गैर–अनुपालन की संख्या में बढ़ोतरी

हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जम्मू में जिला प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में यातायात की स्थिति को सुधारने के लिए लगातार काम कर रहा है, लेकिन यह भी सच है कि प्रयासों के बावजूद जम्मू की सड़कों पर यातायात नियमों का उल्लंघन और गैर–अनुपालन की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे दुर्घटनाएं और संबंधित मौतें हो रही हैं।

इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने कथित तौर पर मोटर वाहन अधिनियम के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रवर्तन अभियान चलाने का आदेश दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, सड़क सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने और भविष्य की कार्रवाई की रणनीति बनाने के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान। जिले में यातायात की स्थिति को सुधारने के लिए ऐसी बैठकें जरूरी हैं, क्योंकि जम्मू में अभी भी ऐसे स्थान हैं जहां यात्री यातायात नियमों की परवाह नहीं करते और इस तरह से वाहन चलाते हैं जैसे कि यह उनकी निजी जागीर हो और वे इस जिले की सड़कों पर कुछ भी कर सकते हैं।

यह अजीब है कि प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी निगरानी और असंख्य यातायात पुलिस टुकड़ियों की तैनाती के बावजूद, क्षेत्र में यातायात प्रबंधन अभी भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हालांकि डीएम जम्मू ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के अलावा अस्पष्ट या छेड़छाड़ की गई नंबर प्लेट वाले वाहनों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है, लेकिन प्रवर्तन दल अपने दृष्टिकोण में सुस्त दिखाई देते हैं क्योंकि इस तरह के निर्देश पहले भी कई बार जारी किए जा चुके हैं, लेकिन सड़कों पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। हितधारकों को चंडीगढ़ यूटी की ट्रैफिक पुलिस से सीख लेने की सलाह दी जाती है, जो यातायात को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और शहर की सड़कों को अपने नागरिकों और आगंतुकों के लिए सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जिन लोगों को चंडीगढ़ में ड्राइविंग का अनुभव है, उन्हें पता होगा कि उस यूटी की ट्रैफिक पुलिस हमेशा ट्रैफिक नियमों और विनियमों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में रखती है ताकि सड़क उपयोगकर्ता दिन के किसी भी समय घूमने में सुरक्षित महसूस करें। ट्रैफिक पुलिस द्वारा किए गए बहुमूल्य प्रयासों के कारण, चंडीगढ़ शहर यातायात नियमों के अनुपालन के लिए एक द्वीप के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। जम्मू जिले में या पूरे यूटी जम्मू और कश्मीर में इसी तरह के प्रयासों का अनुकरण करना समय की मांग है ताकि इस क्षेत्र को भी यातायात प्रबंधन के मामले में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रों में से एक बनाया जा सके।

रमेश सर्राफ धमोरा

भारत वह देश है जहां महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत का खास ख्याल रखा जाता है। अगर हम २१वीं सदी की बात करें तो यहां की महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला काम कर रही है। अब तो भारत की संसद ने भी महिलाओं के लिए लोकसभा व विधानसभाओं में ३३ प्रतिशत आरक्षण का विधेयक पास कर दिया है। इससे आने वाले समय में भारत की राजनीति में महिलाओं की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होनी तय है। देश में महिलाओं को अब सेना में भी महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जाने लगा है। यह महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।

यहां महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार है। महिलायें देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा विकास में भी बराबर की भागीदार हैं। आज के युग में महिला पुरुषों के साथ ही नहीं बल्कि उनसे दो कदम आगे निकल चुकी है। महिलाओं के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुसार महिलाओं को भी पुरुषों के समान जीवन जीने का हक है।भारत में नारी को देवी के रूप में देखा गया है। कहा

विक्रम उपाध्याय
दुनिया तेजी से बदलती है...। और उससे भी ज्यादा तेजी से बदलते हैं वे देश, जो अपने हित के लिए पूरी व्यवस्था बदलने का माद्दा रखते हैं। अमेरिका इस मामले में अकेला देश है, जो खेल का नियम अपने लाभ के लिए बनाता है। राष्ट्रपति ट्रंप अकेले उदाहरण नहीं हैं। कुछ लोग भले ही उनको सनकी मान रहे हों, पर इसके पहले भी अमेरिका फर्स्ट के नारे को साधने के लिए नियमों के साथ खिचापड़ा अमेरिकी हुक्मरानों ने किया है। पिछले चार दशकों में अमेरिकी मनमानेपन के शिकार कई देश हुए हैं। इराक, अफगानिस्तान, ईरान जैसे देश कुछ तो अपने कारण, और बहुत कुछ वाशिंगटन नीति के कारण ही तबाह हुए।

पिछली सदी के ९० के दशक में यह अमेरिका और उसके साथ जुड़े कुछ खास दोस्त ही थे, जिन्होंने द्वाकल प्रस्ताव लाकर पूरी दुनिया के व्यापार को एक साथ अपने इशारे पर चलने का कुचक्र चलाया था।

प्रियंका सौरभ देश में भाषा शिक्षा को लेकर चर्चा जारी है। तमिलनाडु में त्रिभाषा नीति का कड़ा विरोध भाषायी पहचान और केंद्र की नीतियों के बारे में महत्वपूर्ण चिंता को उजागर करता है। वास्तविक शैक्षिक सुधार के लिए भाषा शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाना आवश्यक है, न कि केवल नीतिगत ढांचों पर ध्यान केंद्रित करना है। केंद्र और राज्य के बीच सकारात्मक बातचीत और व्यावहारिक समझौता ही आगे का सबसे अच्छा रास्ता है। आपातकाल के दौरान शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, जिसका अर्थ है कि यह एक संयुक्त जिम्मेदारी है। त्रिभाषा (तीसरी भाषा) से सम्बंधित विवादों के कारण समग्र शिक्षा, जो एक आवश्यक शिक्षा पहल है, के विपरीपेाषण में बाधा नहीं आनी चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–२०२० बहुभाषी शिक्षा को बढ़ाने और भाषायी विविधता की सुरक्षा के उद्देश्य से त्रिभाषा ढांचा प्रस्तुत करती है। आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त २२ आधिकारिक भाषाओं और बोलियों की समृद्ध विविधता के साथ, क्षेत्रीय आवश्यकताओं और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन हासिल करना काफी चुनौतीपूर्ण है। गैर–हिन्दी भाषी राज्यों की चिंताएं

जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। प्राचीन काल से ही यहां महिलाओं को समाज में विशिष्ट आदर एवं सम्मान दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल ०८ मार्च १९११ से पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाना है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस २०२५ का थीम है– कार्रवाई में तेजी लाना।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल २०२३ में भारत में महिलाओं के खिलाफ कुल ४,०५,८६१ अपराध दर्ज किए गए। इनमें सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न के मामले हैं। यह आंकड़े समाज में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति समाज और परिवार की उदासीनता को दर्शाते हैं। २०२२ में ४,४५,२५६ मामले, २०२१ में ४,२८,२७८ मामले २०२० में ३,७१,९०३ मामले दर्ज किए गए थे। आंकड़ों के मुताबिक प्रति एक लाख आबादी पर महिला अपराध की दर ६६.४ फीसदी रिकॉर्ड की गई। भारतीय दंड संहिता के तहत महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा ३१.४ फीसदी जुर्म पति या उसके रिश्तेदारों की क्रूरता के हैं।

रचने का सफल प्रस्ताव किया, कृषि पर ट्रिप्स और व्यापार पर ट्रिम्स लागू कर सभी देशों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की गई। ट्रिप्स प्रावधानों में यहां तक ज्यादाती की गई, कि इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाला देश अपने गरीब किसानों को कोई सब्सिडी न देने पाए। एक तरफ अमेरिका और यूरोप अपने उत्पादों को दुनिया के बाजार में आसानी से उतारने के लिए अपने यहां भारी इनसेंटिव दे रहे थे और दूसरी तरफ भारत जैसे विकासशील देशों पर तरह के प्रतिबंध लगा रहे थे। जब देश में प्रधानमंत्री के रूप में भाजपा के सर्वशक्तिमान नेता अटल बिहारी वाजपेयी विराजमान थे, तब अमेरिका ने मात्रात्मक प्रतिबंध नियमों के बहाने कई वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब मदनलाल खुराना संसदीय कार्य मंत्री थे। उन्होंने मात्रात्मक प्रतिबंध का अमेरिकी फैसले का पुरजोर विरोध किया था, तब उनको अपना पोर्टफोलियो खोना

इसके बाद अपहरण के १९२ फीसदी, शील भंग करने के इरादे से हमले के १८.७ फीसदी और दुष्कर्म के ७.१ फीसदी मामले हैं। पिछले साल देश में जितने मामले सामने आए उनमें से २,२३,६३५ यानी ५० फीसदी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में २०२१ में महिला अपराध के ५६,०८३ और और २०२० में ४९,३८५ मामले दर्ज किए थे। इसके बाद राजस्थान (४०,७३८ और ३४,५३५), महाराष्ट्र (३९,५२६ और ३१,९५४), पश्चिम बंगाल (३५,८८४ और ३६,४३९) और मध्य प्रदेश (३०,६७३ और २५,६४०) रहे थे।

भारत में वर्षों से महिला सुरक्षा से जुड़े कई कानून हैं। इसमें हिंदू विदो रीमैरिज एक्ट १८५६, इंडियन पीनल कोड १८६०, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट १८६१, क्रिस्चियन मैरिज एक्ट १८७२, मैरिड वीमेन प्रॉपर्टी एक्ट १८७४,चाइल्ड मैरिज एक्ट १९२९, स्पेशल मैरिज एक्ट १९५४, हिन्दू मैरिज एक्ट १९५५, फॉरेन मैरिज एक्ट १९६९, इंडियन डाइवोर्स एक्ट १९६९, मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन एक्ट १९८६, नेशनल कमीशन फॉर वुमन एक्ट १९९०, सेक्सुअल हर्रास्पैट ऑफ वुमन एट वर्किंग

पड़ा था। अमेरिका तब पाकिस्तान के प्रेम में था और अपना प्रभाव पाकिस्तान को भारतीय कोप से बचाने में भी करता था। तब जार्ज बुश ने पाकिस्तान को तो अपने हित साधने के लिए एक १६ युद्धक विमान दे दिया, लेकिन भारत के लिए इनकार कर दिया।

राष्ट्रपति ट्रंप व्यापार के नए नियम बनाना और चलाना चाहते हैं। उनके लिए कोई देश उनका अपना नहीं है, भारत भी नहीं। तमाम विशेषज्ञों ने ये दावे किए थे कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों को निभाते हुए ट्रंप भारत के खिलाफ कोई आक्रामक रुख अख्तियार नहीं करेंगे। पर ये सारे कयास धरे के धरे रह गए। जो व्यवहार ट्रंप ईश्यावश मैक्सिको के साथ कर रहे हैं, वही व्यवहार वह भारत के साथ भी करते दिख रहे हैं। जिस तरह से अमानवीय व्यवहार भारत के गैरकानूनी प्रवासियों के साथ ट्रंप प्रशासन ने किया, उसके बाद यह अपेक्षा बेमानी है कि ट्रंप, मोदी सरकार को कोई विशेष छूट देने

नहीं चाहेंगे।

इसके अतिरिक्त, कई राज्यों को इन अतिरिक्त भाषाओं के लिए योग्य शिक्षकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सरकारी स्कूलों में कार्यान्वयन जटिल हो रहा है। उदाहरण के लिए, ओडिशा और केरल के स्कूलों को सीमित उपलब्धता के कारण हिन्दी शिक्षकों को ढूँढ़ने में संघर्ष करना पड़ रहा है। अतिरिक्त भाषा पाठ्यक्रम शुरू करने से भी छात्रों पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे गणित जैसे आवश्यक विषयों में उनकी दक्षता प्रभावित हो सकती है। क्षेत्रीय दलों का प्रतिरोध भाषा नीतियों को अपनाने में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ उत्पन्न करता है। गैर–हिंदी भाषी राज्यों में राजनीतिक समूह अक्सर इन नीतियों को अपने स्थानीय शासन में घुसपैठ के रूप में देखते हैं, जिसके परिणामस्वरूप विरोध होता है। कई ग्रामीण छात्रों को

के ६०५ मामले, पीछा करने की ४७२ मामले और सम्मान से जुड़े अपराध के खिलाफ ४०९ शिकायतें दर्ज कराई गईं। आंकड़ों के मुताबिक, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बलात्कार के मामले भी शामिल हैं। साल २०२३ में बलात्कार और बलात्कार के प्रयास के १,५३७ मामले दर्ज किए गए। इसके बाद गरिमा के अधिकार के तहत ८,५४०, घरेलू हिंसा के ६,२७४, दहेज उत्पीड़न के ४,७९७, छेड़छाड़ के २,३४९,और महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता के १,६१८ मामले दर्ज किए गए।

२०२३ में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले २०२२ की तुलना में कम हुए हैं। २०२२ में महिलाओं के खिलाफ अपराध के ३०,८६४ मामले दर्ज किए गए थे। जबकि २०२३ में यह संख्या घटकर २८,२७८ हो गई। यह एक सकारात्मक संकेत है लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। साल २०२२ के बाद से शिकायतों की संख्या में कमी देखी गई है। जब ३०,८६४ शिकायतें प्राप्त हुई थी, जो २०१४ के बाद से सर्वाधिक आंकड़ा था। जहां तक बात महिलाओं की सुरक्षा की आती है तो पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व निर्णयों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रबंध किए हैं। आज भारत में

के ६०५ मामले, पीछा करने की ४७२ मामले और सम्मान से जुड़े अपराध के खिलाफ ४०९ शिकायतें दर्ज कराई गईं। आंकड़ों के मुताबिक, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बलात्कार के मामले भी शामिल हैं। साल २०२३ में बलात्कार और बलात्कार के प्रयास के १,५३७ मामले दर्ज किए गए। इसके बाद गरिमा के अधिकार के तहत ८,५४०, घरेलू हिंसा के ६,२७४, दहेज उत्पीड़न के ४,७९७, छेड़छाड़ के २,३४९,और महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता के १,६१८ मामले दर्ज किए गए।

२०२३ में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले २०२२ की तुलना में कम हुए हैं। २०२२ में महिलाओं के खिलाफ अपराध के ३०,८६४ मामले दर्ज किए गए थे। जबकि २०२३ में यह संख्या घटकर २८,२७८ हो गई। यह एक सकारात्मक संकेत है लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। साल २०२२ के बाद से शिकायतों की संख्या में कमी देखी गई है। जब ३०,८६४ शिकायतें प्राप्त हुई थी, जो २०१४ के बाद से सर्वाधिक आंकड़ा था। जहां तक बात महिलाओं की सुरक्षा की आती है तो पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व निर्णयों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रबंध किए हैं। आज भारत में

के ६०५ मामले, पीछा करने की ४७२ मामले और सम्मान से जुड़े अपराध के खिलाफ ४०९ शिकायतें दर्ज कराई गईं। आंकड़ों के मुताबिक, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बलात्कार के मामले भी शामिल हैं। साल २०२३ में बलात्कार और बलात्कार के प्रयास के १,५३७ मामले दर्ज किए गए। इसके बाद गरिमा के अधिकार के तहत ८,५४०, घरेलू हिंसा के ६,२७४, दहेज उत्पीड़न के ४,७९७, छेड़छाड़ के २,३४९,और महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता के १,६१८ मामले दर्ज किए गए।

२०२३ में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले २०२२ की तुलना में कम हुए हैं। २०२२ में महिलाओं के खिलाफ अपराध के ३०,८६४ मामले दर्ज किए गए थे। जबकि २०२३ में यह संख्या घटकर २८,२७८ हो गई। यह एक सकारात्मक संकेत है लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। साल २०२२ के बाद से शिकायतों की संख्या में कमी देखी गई है। जब ३०,८६४ शिकायतें प्राप्त हुई थी, जो २०१४ के बाद से सर्वाधिक आंकड़ा था। जहां तक बात महिलाओं की सुरक्षा की आती है तो पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व निर्णयों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रबंध किए हैं। आज भारत में

के ६०५ मामले, पीछा करने की ४७२ मामले और सम्मान से जुड़े अपराध के खिलाफ ४०९ शिकायतें दर्ज कराई गईं। आंकड़ों के मुताबिक, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बलात्कार के मामले भी शामिल हैं। साल २०२३ में बलात्कार और बलात्कार के प्रयास के १,५३७ मामले दर्ज किए गए। इसके बाद गरिमा के अधिकार के तहत ८,५४०, घरेलू हिंसा के ६,२७४, दहेज उत्पीड़न के ४,७९७, छेड़छाड़ के २,३४९,और महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता के १,६१८ मामले दर्ज किए गए।

२०२३ में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले २०२२ की तुलना में कम हुए हैं। २०२२ में महिलाओं के खिलाफ अपराध के ३०,८६४ मामले दर्ज किए गए थे। जबकि २०२३ में यह संख्या घटकर २८,२७८ हो गई। यह एक सकारात्मक संकेत है लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। साल २०२२ के बाद से शिकायतों की संख्या में कमी देखी गई है। जब ३०,८६४ शिकायतें प्राप्त हुई थी, जो २०१४ के बाद से सर्वाधिक आंकड़ा था। जहां तक बात महिलाओं की सुरक्षा की आती है तो पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व निर्णयों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रबंध किए हैं। आज भारत में

के ६०५ मामले, पीछा करने की ४७२ मामले और सम्मान से जुड़े अपराध के खिलाफ ४०९ शिकायतें दर्ज कराई गईं। आंकड़ों के मुताबिक, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बलात्कार के मामले भी शामिल हैं। साल २०२३ में बलात्कार और बलात्कार के प्रयास के १,५३७ मामले दर्ज किए गए। इसके बाद गरिमा के अधिकार के तहत ८,५४०, घरेलू हिंसा के ६,२७४, दहेज उत्पीड़न के ४,७९७, छेड़छाड़ के २,३४९,और महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता के १,६१८ मामले दर्ज किए गए।

२०२३ में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले २०२२ की तुलना में कम हुए हैं। २०२२ में महिलाओं के खिलाफ अपराध के ३०,८६४ मामले दर्ज किए गए थे। जबकि २०२३ में यह संख्या घटकर २८,२७८ हो गई। यह एक सकारात्मक संकेत है लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। साल २०२२ के बाद से शिकायतों की संख्या में कमी देखी गई है। जब ३०,८६४ शिकायतें प्राप्त हुई थी, जो २०१४ के बाद से सर्वाधिक आंकड़ा था। जहां तक बात महिलाओं की सुरक्षा की आती है तो पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व निर्णयों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रबंध किए हैं। आज भारत में

महिलाएं पहले की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित है।

हम एक तरफ महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा देकर उन्हे आगे बढ़ा रहें है। वहीं दूसरी तरफ उनके साथ अत्याचार की घटनाओं में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आये दिन हमें महिलाओं के साथ बलात्कार, दुर्व्यवहार होने की घटनाये सुनने को मिलती रहती है। ऐसी घटनाओं से महिला सशक्तीकरण के अभियान को धक्का लगता हैं। देश में महिलाओं के प्रति खराब होते माहौल को बदलने की महिलाओं सिर्फ सरकार की ही नहीं अपितु हर आम आदमी की भी है। हम सभी को आगे आकर महिला सुरक्षा की लड़ाई में महिलाओं का साथ देना होगा तभी देश की मातृ शक्ति सर उठा कर शान से चल सकेगीं। अब महिलाओं को समझाना होगा कि आज समाज में उनकी दयनीय स्थिति समाज में चली आ रही परम्पराओं का परिणाम है। इन परम्पराओं को बदलने का बीड़ा स्वयं महिलाओं को ही उठाना होगा। तभी समाज में उनके प्रति सोच बदल पाएगी।

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

के ६०५ मामले, पीछा करने की ४७२ मामले और सम्मान से जुड़े अपराध के खिलाफ ४०९ शिकायतें दर्ज कराई गईं। आंकड़ों के मुताबिक, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बलात्कार के मामले भी शामिल हैं। साल २०२३ में बलात्कार और बलात्कार के प्रयास के १,५३७ मामले दर्ज किए गए। इसके बाद गरिमा के अधिकार के तहत ८,५४०, घरेलू हिंसा के ६,२७४, दहेज उत्पीड़न के ४,७९७, छेड़छाड़ के २,३४९,और महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता के १,६१८ मामले दर्ज किए गए।

२०२३ में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले २०२२ की तुलना में कम हुए हैं। २०२२ में महिलाओं के खिलाफ अपराध के ३०,८६४ मामले दर्ज किए गए थे। जबकि २०२३ में यह संख्या घटकर २८,२७८ हो गई। यह एक सकारात्मक संकेत है लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। साल २०२२ के बाद से शिकायतों की संख्या में कमी देखी गई है। जब ३०,८६४ शिकायतें प्राप्त हुई थी, जो २०१४ के बाद से सर्वाधिक आंकड़ा था। जहां तक बात महिलाओं की सुरक्षा की आती है तो पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व निर्णयों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रबंध किए हैं। आज भारत में

के ६०५ मामले, पीछा करने की ४७२ मामले और सम्मान से जुड़े अपराध के खिलाफ ४०९ शिकायतें दर्ज कराई गईं। आंकड़ों के मुताबिक, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बलात्कार के मामले भी शामिल हैं। साल २०२३ में बलात्कार और बलात्कार के प्रयास के १,५३७ मामले दर्ज किए गए। इसके बाद गरिमा के अधिकार के तहत ८,५४०, घरेलू हिंसा के ६,२७४, दहेज उत्पीड़न के ४,७९७, छेड़छाड़ के २,३४९,और महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता के १,६१८ मामले दर्ज किए गए।

२०२३ में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले २०२२ की तुलना में कम हुए हैं। २०२२ में महिलाओं के खिलाफ अपराध के ३०,८६४ मामले दर्ज किए गए थे। जबकि २०२३ में यह संख्या घटकर २८,२७८ हो गई। यह एक सकारात्मक संकेत है लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। साल २०२२ के बाद से शिकायतों की संख्या में कमी देखी गई है। जब ३०,८६४ शिकायतें प्राप्त हुई थी, जो २०१४ के बाद से सर्वाधिक आंकड़ा था। जहां तक बात महिलाओं की सुरक्षा की आती है तो पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व निर्णयों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रबंध किए हैं। आज भारत में

के ६०५ मामले, पीछा करने की ४७२ मामले और सम्मान से जुड़े अपराध के खिलाफ ४०९ शिकायतें दर्ज कराई गईं। आंकड़ों के मुताबिक, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बलात्कार के मामले भी शामिल हैं। साल २०२३ में बलात्कार और बलात्कार के प्रयास के १,५३७ मामले दर्ज किए गए। इसके बाद गरिमा के अधिकार के तहत ८,५४०, घरेलू हिंसा के ६,२७४, दहेज उत्पीड़न के ४,७९७, छेड़छाड़ के २,३४९,और महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता के १,६१८ मामले दर्ज किए गए।

२०२३ में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले २०२२ की तुलना में कम हुए हैं। २०२२ में महिलाओं के खिलाफ अपराध के ३०,८६४ मामले दर्ज किए गए थे। जबकि २०२३ में यह संख्या घटकर २८,२७८ हो गई। यह एक सकारात्मक संकेत है लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। साल २०२२ के बाद से शिकायतों की संख्या में कमी देखी गई है। जब ३०,८६४ शिकायतें प्राप्त हुई थी, जो २०१४ के बाद से सर्वाधिक आंकड़ा था। जहां तक बात महिलाओं की सुरक्षा की आती है तो पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व निर्णयों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रबंध किए हैं। आज भारत में

के ६०५ मामले, पीछा करने की ४७२ मामले और सम्मान से जुड़े अपराध के खिलाफ ४०९ शिकायतें दर्ज कराई गईं। आंकड़ों के मुताबिक, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बलात्कार के मामले भी शामिल हैं। साल २०२३ में बलात्कार और बलात्कार के प्रयास के १,५३७ मामले दर्ज किए गए। इसके बाद गरिमा के अधिकार के तहत ८,५४०, घरेलू हिंसा के ६,२७४, दहेज उत्पीड़न के ४,७९७, छेड़छाड़ के २,३४९,और महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता के १,६१८ मामले दर्ज किए गए।

२०२३ में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले २०२२ की तुलना में कम हुए हैं। २०२२ में महिलाओं के खिलाफ अपराध के ३०,८६४ मामले दर्ज किए गए थे। जबकि २०२३ में यह संख्या घटकर २८,२७८ हो गई। यह एक सकारात्मक संकेत है लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। साल २०२२ के बाद से शिकायतों की संख्या में कमी देखी गई है। जब ३०,८६४ शिकायतें प्राप्त हुई थी, जो २०१४ के बाद से सर्वाधिक आंकड़ा था। जहां तक बात महिलाओं की सुरक्षा की आती है तो पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व निर्णयों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रबंध किए हैं। आज भारत में

देहात संदेश

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल

एजेंसी नई दिल्ली। भारत बनाम न्यूजीलैंड फाइनल मैच ९ मार्च को खेला जाएगा. मैच भारतीय समयनुसार दोपहर 2 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा. **भारत की संभावित एकादश:** रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेट कीपर), हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.

न्यूजीलैंड की संभावित एकादश: विल यंग, रचिन रविंद, केन विलियमसन, डेरिल मिशेल, टॉम लेथम (विकेट कीपर), र्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटरन (कप्तान), मैट हेनरी, काइल जैमिंसन, विल ओरीके.

स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने भारतीय दल के लिए किया विदाई समारोह का आयोजन

नई दिल्ली। स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में भारतीय दल के लिए भव्य विदाई समारोह आयोजित किया। समारोह में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामलों एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, स्पेशल ओलंपिक्स भारत की अध्यक्ष डॉ. मल्लिका नड्डा और कार्यकारी निदेशक डॉ. वी.के. महेंदु उपस्थित रहे। इटली के ट्यूरिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025



में 49 सदस्यीय दल, जिसमें 30 एथलीट और 19 सहयोगी स्टाफ शामिल हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। 8 से 15 मार्च तक आयोजित होने वाले इन खेलों में भारतीय दल छह खेल स्पर्धाओं एल्याइन स्कीइंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, फ्लोबाॅल, शॉर्ट-ट्रैक स्पीड स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग और स्नोशूइंग में भाग लेगा। इस वैश्विक प्रतियोगिता में 102 देशों के 1500 से अधिक एथलीट 8 खेल विधाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगे। भारतीय दल 6 मार्च को इटली के लिए रवाना होगा, जहां वे पूरी ताकत से प्रतिस्पर्धा करेंगे।

रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप में रायगढ़ के सचिन चौहान का हुआ चयन

रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ द्वारा सीनियर एलीट ग्रुप इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों का चयन किया गया, जिसमें रायगढ़ के उभरते क्रिकेटर सचिन चौहान का नाम भी शामिल है। सचिन चौहान ने अपने शानदार प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को प्रभावित किया और लगातार सातवीं बार रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप में जगह बनाई है। छत्तीसगढ़ सीनियर प्लेट कबाड़ंड टीम के लिए चुने गए खिलाड़ियों को 5 मार्च को सुबह 11 बजे तक रायपुर के होटल बेबीलोन कैपिटल में रिपोर्ट करना होगा, जिसके बाद दोपहर 2 बजे से आरखीसीए ग्राउंड, रायपुर में अभ्यास सत्र शुरू होगा। खिलाड़ियों को अपने आधार कार्ड, सीएससीएस यूनिफॉर्म और किट बैग साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं। सचिन चौहान का क्रिकेट सफर आसान नहीं रहा, लेकिन अपनी लगन, अनुशासन और कड़ी मेहनत से उन्होंने खुद को साबित किया। रणजी ट्रॉफी के पिछले सत्र में उन्होंने एक ही मैच में 8 विकेट लेकर चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा था। हालाँकि, निजी कारणों से उन्हें एक मैच में खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अपने प्रदर्शन के दम पर उन्होंने फिर से टीम में जगह बनाई। बता दें एलीट ग्रुप टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ की रणजी ट्रॉफी टीम में सीधे चयनित होने का मौका मिलेगा, जिससे सचिन सहित अन्य खिलाड़ियों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण प्रतियोगिता साबित हो सकती है।

धर्मशाला में पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों ने दूसरे दिन बहाया जमकर पसीना

धर्मशाला। धर्मशाला में मौसम साफ होते ही धर्मशाला के खूबसूरत एचपीसीए स्टेडियम में पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों ने दूसरे दिन भी जमकर अभ्यास किया। आईपीएल 2025 के लिए पंजाब किंग्स की टीम इन दिनों धर्मशाला में है। 22 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने स्टेडियम में पांच दिवसीय अभ्यास सत्र शुरू कर दिया है। टीम के स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल, बल्लेबाज प्रभुमिशनर सिंह और ऑलराउंडर सुशांक सिंह पहले ही धर्मशाला पहुंच चुके थे। हालांकि, बीते दिनों खराब मौसम के चलते खिलाड़ियों को अभ्यास करने में परेशानी का सामना करना पड़ा था लेकिन अब मौसम अनुकूल होते ही खिलाड़ी मैदान पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। आईपीएल मुकाबलों के मद्देनजर किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाड़ी रणनीति बनाने और अपनी तकनीक को धार देने में जुटे हुए हैं। टीम प्रबंधन के अनुसार, धर्मशाला के इस शानदार मैदान में अभ्यास करने से खिलाड़ियों को मैच कंडीशंस के अनुरूप खुद को तैयार करने का बेहतरी मौका मिलेगा। उल्लेखनीय है कि एचपीसीए स्टेडियम अपनी खूबसूरती और पहाड़ों के बीच बसे होने के कारण क्रिकेट प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए हमेशा से खास आकर्षण का केंद्र रहा है।

एजेंसी हैदराबाद। 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक की तैयारियों और 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया 7-8 मार्च को हैदराबाद में एक उच्च स्तरीय चिंतन शिबिर की अध्यक्षता करेंगे।

यह दो दिवसीय विचार-विमर्श सत्र कान्हा शांतिवनम में आयोजित किया जाएगा, जहां विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्री, वरिष्ठ खेल प्रशासक, प्रमुख सरकारी अधिकारी और खेल विशेषज्ञ एक मंच पर आकर भारत को वैश्विक खेल शक्ति बनाने की रणनीति तैयार करेंगे। इस दौरान खेल प्रशासन को सशक्त बनाने, जमीनी

में विभिन्न हितधारकों के साथ

रणनीतिक चर्चा करेंगे। राज्यों के प्रतिनिधि अपने बेहदरीन मॉडल और

नवाचारों को साझा करेंगे, जिससे

राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी खेल नीतियों

का निर्माण किया जा सके।

चिंतन शिविर के प्रमुख फोकस क्षेत्र-

- केंद्र सरकार की विभिन्न खेल

प्रणालियों के विकास, समावेशिता

बढ़ाने और सहयोगी प्रयासों को गति

देने पर विचार-विमर्श होगा।

डॉ. मांडविया, इस चिंतन शिविर

में विभिन्न हितधारकों के साथ

रणनीतिक चर्चा करेंगे। राज्यों के

प्रतिनिधि अपने बेहदरीन मॉडल और

नवाचारों को साझा करेंगे, जिससे

राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी खेल नीतियों

का निर्माण किया जा सके।

चिंतन शिविर के प्रमुख फोकस क्षेत्र-

- केंद्र सरकार की विभिन्न खेल

प्रणालियों के विकास, समावेशिता

बढ़ाने और सहयोगी प्रयासों को गति

देने पर विचार-विमर्श होगा।

डॉ. मांडविया, इस चिंतन शिविर

में विभिन्न हितधारकों के साथ

रणनीतिक चर्चा करेंगे। राज्यों के

प्रतिनिधि अपने बेहदरीन मॉडल और

नवाचारों को साझा करेंगे, जिससे

राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी खेल नीतियों

का निर्माण किया जा सके।

चिंतन शिविर के प्रमुख फोकस क्षेत्र-

- केंद्र सरकार की विभिन्न खेल

प्रणालियों के विकास, समावेशिता

बढ़ाने और सहयोगी प्रयासों को गति

देने पर विचार-विमर्श होगा।

डॉ. मांडविया, इस चिंतन शिविर

में विभिन्न हितधारकों के साथ

रणनीतिक चर्चा करेंगे। राज्यों के

प्रतिनिधि अपने बेहदरीन मॉडल और

नवाचारों को साझा करेंगे, जिससे

राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी खेल नीतियों

का निर्माण किया जा सके।

चिंतन शिविर के प्रमुख फोकस क्षेत्र-

- केंद्र सरकार की विभिन्न खेल

प्रणालियों के विकास, समावेशिता

बढ़ाने और सहयोगी प्रयासों को गति

देने पर विचार-विमर्श होगा।

डॉ. मांडविया, इस चिंतन शिविर

में विभिन्न हितधारकों के साथ

रणनीतिक चर्चा करेंगे। राज्यों के

प्रतिनिधि अपने बेहदरीन मॉडल और

नवाचारों को साझा करेंगे, जिससे

राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी खेल नीतियों

का निर्माण किया जा सके।

चिंतन शिविर के प्रमुख फोकस क्षेत्र-

- केंद्र सरकार की विभिन्न खेल

प्रणालियों के विकास, समावेशिता

बढ़ाने और सहयोगी प्रयासों को गति

देने पर विचार-विमर्श होगा।

डॉ. मांडविया, इस चिंतन शिविर

में विभिन्न हितधारकों के साथ

रणनीतिक चर्चा करेंगे। राज्यों के

प्रतिनिधि अपने बेहदरीन मॉडल और

नवाचारों को साझा करेंगे, जिससे

राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी खेल नीतियों

का निर्माण किया जा सके।

चिंतन शिविर के प्रमुख फोकस क्षेत्र-

- केंद्र सरकार की विभिन्न खेल

प्रणालियों के विकास, समावेशिता

बढ़ाने और सहयोगी प्रयासों को गति

देने पर विचार-विमर्श होगा।

डॉ. मांडविया, इस चिंतन शिविर

में विभिन्न हितधारकों के साथ

रणनीतिक चर्चा करेंगे। राज्यों के

प्रतिनिधि अपने बेहदरीन मॉडल और

नवाचारों को साझा करेंगे, जिससे

राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी खेल नीतियों

का निर्माण किया जा सके।

चिंतन शिविर के प्रमुख फोकस क्षेत्र-

- केंद्र सरकार की विभिन्न खेल

प्रणालियों के विकास, समावेशिता

बढ़ाने और सहयोगी प्रयासों को गति

देने पर विचार-विमर्श होगा।

डॉ. मांडविया, इस चिंतन शिविर

में विभिन्न हितधारकों के साथ

रणनीतिक चर्चा करेंगे। राज्यों के

प्रतिनिधि अपने बेहदरीन मॉडल और

नवाचारों को साझा करेंगे, जिससे

राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी खेल नीतियों

का निर्माण किया जा सके।

चिंतन शिविर के प्रमुख फोकस क्षेत्र-

- केंद्र सरकार की विभिन्न खेल

प्रणालियों के विकास, समावेशिता

बढ़ाने और सहयोगी प्रयासों को गति

देने पर विचार-विमर्श होगा।

डॉ. मांडविया, इस चिंतन शिविर

में विभिन्न हितधारकों के साथ

रणनीतिक चर्चा करेंगे। राज्यों के

प्रतिनिधि अपने बेहदरीन मॉडल और

नवाचारों को साझा करेंगे, जिससे

राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी खेल नीतियों

का निर्माण किया जा सके।

चिंतन शिविर के प्रमुख फोकस क्षेत्र-

- केंद्र सरकार की विभिन्न खेल

प्रणालियों के विकास, समावेशिता

बढ़ाने और सहयोगी प्रयासों को गति

देने पर विचार-विमर्श होगा।

डॉ. मांडविया, इस चिंतन शिविर

में विभिन्न हितधारकों के साथ

रणनीतिक चर्चा करेंगे। राज्यों के

प्रतिनिधि अपने बेहदरीन मॉडल और

नवाचारों को साझा करेंगे, जिससे

राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी खेल नीतियों

का निर्माण किया जा सके।

चिंतन शिविर के प्रमुख फोकस क्षेत्र-

- केंद्र सरकार की विभिन्न खेल

प्रणालियों के विकास, समावेशिता

बढ़ाने और सहयोगी प्रयासों को गति

देने पर विचार-विमर्श होगा।

डॉ. मांडविया, इस चिंतन शिविर

में विभिन्न हितधारकों के साथ

रणनीतिक चर्चा करेंगे। राज्यों के

प्रतिनिधि अपने बेहदरीन मॉडल और

नवाचारों को साझा करेंगे, जिससे

राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी खेल नीतियों

का निर्माण किया जा सके।

चिंतन शिविर के प्रमुख फोकस क्षेत्र-

- केंद्र सरकार की विभिन्न खेल

प्रणालियों के विकास, समावेशिता

बढ़ाने और सहयोगी प्रयासों को गति

देने पर विचार-विमर्श होगा।

डॉ. मांडविया, इस चिंतन शिविर

में विभिन्न हितधारकों के साथ

रणनीतिक चर्चा करेंगे। राज्यों के

प्रतिनिधि अपने बेहदरीन मॉडल और

नवाचारों को साझा करेंगे, जिससे

राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी खेल नीतियों

का निर्माण किया जा सके।

चिंतन शिविर के प्रमुख फोकस क्षेत्र-

- केंद्र सरकार की विभिन्न खेल

प्रणालियों के विकास, समावेशिता

बढ़ाने और सहयोगी प्रयासों को गति

देने पर विचार-विमर्श होगा।

डॉ. मांडविया, इस चिंतन शिविर

में विभिन्न हितधारकों के साथ

रणनीतिक चर्चा करेंगे। राज्यों के

प्रतिनिधि अपने बेहदरीन मॉडल और

नवाचारों को साझा करेंगे, जिससे

राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी खेल नीतियों

का निर्माण किया जा सके।

चिंतन शिविर के प्रमुख फोकस क्षेत्र-

- केंद्र सरकार की विभिन्न खेल

प्रणालियों के विकास, समावेशिता

बढ़ाने और सहयोगी प्रयासों को गति

देने पर विचार-विमर्श होगा।

डॉ. मांडविया, इस चिंतन शिविर

में विभिन्न हितधारकों के साथ

रणनीतिक चर्चा करेंगे। राज्यों के

प्रतिनिधि अपने बेहदरीन मॉडल और

नवाचारों को साझा करेंगे, जिससे

राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी खेल नीतियों

का निर्माण किया जा सके।

चिंतन शिविर के प्रमुख फोकस क्षेत्र-

- केंद्र सरकार की विभिन्न खेल

प्रणालियों के विकास, समावेशिता

बढ़ाने और सहयोगी प्रयासों को गति

देने पर विचार-विमर्श होगा।

डॉ. मांडविया, इस चिंतन शिविर

में विभिन्न हितधारकों के साथ

रणनीतिक चर्चा करेंगे। राज्यों के

प्रतिनिधि अपने बेहदरीन मॉडल और

नवाचारों को साझा करेंगे, जिससे

राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी खेल नीतियों

का निर्माण किया जा सके।

चिंतन शिविर के प्रमुख फोकस क्षेत्र-

- केंद्र सरकार की विभिन्न खेल

प्रणालियों के विकास, समावेशिता

बढ़ाने और सहयोगी प्रयासों को गति

देने पर विचार-विमर्श होगा।

डॉ. मांडविया, इस चिंतन शिविर

में विभिन्न हितधारकों के साथ

रणनीतिक चर्चा करेंगे। राज्यों के

प्रतिनिधि अपने बेहदरीन मॉडल और

नवाचारों को साझा करेंगे, जिससे

राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी खेल नीतियों

का निर्माण किया जा सके।

चिंतन शिविर के प्रमुख फोकस क्षेत्र-

- केंद्र सरकार की विभिन्न खेल

प्रणालियों के विकास, समावेशिता

बढ़ाने और सहयोगी प्रयासों को गति

देने पर विचार-विमर्श होगा।

डॉ. मांडविया, इस चिंतन शिविर

में विभिन्न हितधारकों के साथ

रणनीतिक चर्चा करेंगे। राज्यों के

प्रतिनिधि अपने बेहदरीन मॉडल और

नवाचारों को साझा करेंगे, जिससे

राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी खेल नीतियों

का निर्माण किया जा सके।

चिंतन शिविर के प्रमुख फोकस क्षेत्र-

- केंद्र सरकार की विभिन्न खेल

प्रणालियों के विकास, समावेशिता

बढ़ाने और सहयोगी प्रयासों को गति

देने पर विचार-विमर्श होगा।

डॉ. मांडविया, इस चिंतन शिविर

अमेरिका टैरिफ के लिए यूरोपीय संघ ने जवाब तैयार किया - मैक्रोन

मॉस्को। यूरोपीय संघ अमेरिकी टैरिफ के लिए जवाब तैयार कर रहा है, लेकिन अभी भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को यह कदम उठाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रोन ने यह बात कही। श्री मैक्रोन ने बी.एफ.एम.टी.वी. द्वारा प्रसारित भाषण में कहा, 'हमें तैयार रहना चाहिए अगर अमेरिका यूरोपीय वस्तुओं पर टैरिफ लगाता है, जैसा कि उसने अभी कनाडा और मैक्सिको के साथ किया है। यह निर्णय हमारे और अमेरिकी अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अस्पष्ट है और हमारे कुछ उद्योगों पर इसके परिणाम होंगे। हम भी इसका उत्तर दिए बिना नहीं रहेंगे। जबकि हम अपने यूरोपीय भागीदारों के साथ जवाब तैयार करते हैं, हम अमेरिकी राष्ट्रपति को मनाने के लिए हर संभव प्रयास करना जारी रखते हैं।' श्री ट्रम्प ने फरवरी में कहा कि उनका प्रशासन बहुत जल्द यूरोपीय संघ से आयात पर नए 25 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा करेगा, जिसमें ऑटोमोबाइल भी शामिल हैं।

तुर्की और अमेरिकी राष्ट्रपतियों के सलाहकारों ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर की चर्चा

अंकारा। तुर्की और अमेरिकी राष्ट्रपतियों के सलाहकारों ने द्विपक्षीय संबंधों और अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए टेलीफोन पर बातचीत की, तुर्की मीडिया ने यह जानकारी दी। हुरियत अखबार की रिपोर्ट के अनुसार विदेश नीति और सुरक्षा पर तुर्की के राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार अकिफ कैगाटे किलिक ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज से बात की। रिपोर्ट में कहा गया है कि किलिक और वाल्ट्ज ने तुर्की और अमेरिका के बीच संबंधों की स्थिति के साथ-साथ प्रासंगिक वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की।



दक्षिण कोरिया के नागरिक क्षेत्र में गोले गिरने से 7 लोग घायल

सियोल। दक्षिण कोरिया के नागरिक क्षेत्र में गोले गिरने से सात लोग घायल हो गए। स्थानीय प्रसारक वाईटीएन के गुरुवार को यह जानकारी दी। राजधानी सियोल से करीब 40 किलोमीटर उत्तर में अंतर-कोरियाई सीमावर्ती शहर पोचेओन में स्थानीय समानानुसार सुबह करीब 10:०0 बजे नागरिक घरों पर दो गोले गिरे। जिससे चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और तीन अन्य को मामूली चोटें आईं। योन्हाप समाचार एजेंसी के अनुसार दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने पोचेओन में एक संयुक्त लाइव-फायर अभ्यास किया, जिसमें टैंक, स्व-चालित हॉवित्जर, हेलीकॉप्टर और स्टील्थ जेट जैसे 160 से अधिक सैन्य हार्डवेयर जुटाए गए।



ट्रंप ने इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर हमास को दी ‘आखिरी चेतावनी’

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराजली बंधकों की रिहाई को लेकर आज हमास को ‘आखिरी चेतावनी’ दी है। श्री ट्रंप ने सोशल प्लेटफॉर्म ट्विथ पर एक पोस्ट में लिखा, मैं इजराजल को वह सब कुछ भेज रहा हूं जो उसे काम पूरा करने के लिए चाहिए, अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो हमास का एक भी सदस्य सुरक्षित नहीं रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पोस्ट में लिखा, शालोम हमास का इसका अर्थ है नमस्ते और अलविदा - आप दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं। सभी बंधकों को अभी रिहा करें, बाद में नहीं, और जिन लोगों की आपने हत्या की है, उनके शवों को तुरंत लौटा दें, अन्यथा आपके लिए सब खत्म हो जाएगा। केवल बीमार और विकृत मानसिकता के लोग ही शवों को रखते हैं, और आप ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं इजरायल को वह सब कुछ भेज रहा हूं जो उसे काम पूरा करने के लिए चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमास का एक भी सदस्य सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं अभी आपके पूर्व बंधकों से मिला हूँ, जिनकी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी है। यह आपको आखिरी चेतावनी है।उन्होंने नागरिकों को भी धमकाते हुए कहा, साथ ही, गाजा के लोगों के लिए कहा कि उनके लिए एक सुंदर भविष्य उनका इंतजार कर रहा है, लेकिन तब नहीं जब आप बंधकों को रखेंगे, अगर आप ऐसा करेंगे, तो आप खत्म हो जाएंगे। समझदारी से फैसला लें। बंधकों को अभी रिहा करें, नहीं तो बाद में आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा।

डेनमार्क ने ट्रंप को दिया दो टूक जवाब, बोला ‘ग्रीनलैंड कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं होगा’

एजेंसी ओस्लो। डेनमार्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने के लिए किए गए नए प्रयासों को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने घोषणा की कि उनका प्रशासन ग्रीनलैंड के लोगों के अपने भविष्य को निर्धारित करने के अधिकार का पुरजोर समर्थन करेगा। उन्होंने कहा, और यदि आप चाहें, तो हम आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वागत करते हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने ट्रंप के बयान को लेकर डेनमार्क की स्थिति को स्पष्ट किया और कहा कि ग्रीनलैंड का भविष्य केवल वहां के लोगों का फैसला होगा। उन्होंने कहा, «ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड के लोगों का है। यह एक ऐसा रख है जिसका हम डेनिश सरकार की ओर से बहुत दृढ़ता से समर्थन करते हैं। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूट एगोडे ने भी ट्रंप के दावे को पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ग्रीनलैंड के लोग अमेरिका का हिस्सा बनने की इच्छा नहीं रखते हैं। डेनमार्क के रक्षा मंत्री



बड़ा द्वीप है, 1953 तक डेनमार्क का उपनिवेश था। उसके बाद यह डेनमार्क का अभिन हिस्सा बन गया और ग्रीनलैंड के लोगों को डेनिश

वैश्विक आतंकवाद सूचकांक-2025 में पाकिस्तान दूसरे स्थान पर

एजेंसी इस्लामाबाद। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक-2025 में पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (आईईपी) ने पिछले 17 वर्ष की घटनाओं के आधार पर रिपोर्ट जारी की है। इसमें 163 देशों को शामिल किया गया है। पाकिस्तान में यह लगातार पांचवां वर्ष है, जब आतंकवाद से संबंधित मौतों में वृद्धि दर्ज की गई है। पाकिस्तान के लिए पिछले दशक में साल-दर-साल यह सबसे बड़ी वृद्धि है।डान समाचार पत्र की खबर के अनुसार रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में पिछले वर्ष आतंकवादी हमलों में मरने वालों की संख्या 45 प्रतिशत बढ़कर 1,081 हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार 45 देशों की स्थिति बेहद खराब हो रही है और 34 देशों की स्थिति में कुछ सुधार हो रहा है। चार



सबसे घातक आतंकवादी समूहों ने 2024 में अपनी हिंसा तेज की। इससे मृत्यु दर में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पश्चिम में आतंकवादी समूह हावी हो गए हैं, जो पिछले पांच वर्षों में 93 प्रतिशत घातक हमलों के लिए जिम्मेदार हैं। ईरान में

आतंकवाद से होने वाली मौतों में वृद्धि हुई है। आतंकवाद से सबसे ज्यादा मौतें बुर्किना फासो,

आया है। टीटीपी के हमलों से होने वाली मौतों में 90 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह संगठन 2024 में भी पाकिस्तान में 52 प्रतिशत मौतों के लिए जिम्मेदार था। पिछले साल टीटीपी ने 482 हमले किए, जिसके परिणामस्वरूप 558 मौतें हुईं, जो पिछले वर्ष की 293 मौतों से 91 प्रतिशत अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।अफगानिस्तान से संचालित आतंकवादी समूहों ने बलूचिस्तान और खैबर-पख्तुन्खा प्रांत को सबसे अधिक निशाना बनाया है। पाकिस्तान सरकार ने इनसे निपटने के लिए ऑपरेशन आजम-ए-इस्तेहकम शुरू किया है।

मलाला यूसुफजई ने पैतृक गांव का दौरा किया

एजेंसी इस्लामाबाद। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने खैबर पख्तुन्खा प्रांत के शांगला जिले के अपने पैतृक गांव बरकाना शाहपुर का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय समुदाय के साथ बातचीत की। मलाला इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचीं। उनके पिता जियाउद्दीन यूसुफजई और मां तूर पेकाई भी थे। शांगला जिला स्वात घाटी में है। यह घाटी दुनिया में मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। यह घाटी लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद से ग्रस्त रही है। मलाला पर इसी घाटी में आतंकी हमला हुआ था। द न्यूज अखबार के अनुसार, बाल अधिकार कार्यकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई का जन्म 12 जुलाई, 1997 को पाकिस्तान की स्वात घाटी के मिंगोरा कस्बे में हुआ था। उनके परिवार और स्कूली बच्चों ने मलाला का भावनात्मक स्वागत किया। मलाला अपने रिश्तेदारों से भी मिलीं। अपनी



यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव में मलाला ने मलाला यूसुफजई स्कूल का दौरा किया। उन्होंने छात्र-छात्रों से मुलाकात की। उनकी समस्याओं को सुना। इस अवसर पर छात्रों ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उर्दू और परतों में देशभक्ति गीत और भाषण प्रस्तुत किए। मलाला ने स्कूल प्रशासन के प्रयासों की सराहना की और अच्छे प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने शांगला जैसे

कस्बों के इलाकों में बच्चों, विशेषकर युवा लड़कियों के लिए शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। मलाला ने शाहपुर गर्ल्स हाईस्कूल में एक कार्यक्रम में भी भाग लिया। मलाला यूसुफजई ने जिंदगी ट्रस्ट के संस्थापक शहजाद रॉय के योगदान को सराहा। दूरदराज के इलाकों में बच्चों, विशेषकर युवा लड़कियों के लिए शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। मलाला ने शाहपुर गर्ल्स हाईस्कूल में एक कार्यक्रम में भी भाग लिया। मलाला यूसुफजई ने जिंदगी ट्रस्ट के संस्थापक शहजाद रॉय के योगदान को सराहा।

राष्ट्रपति दिसानायके के निमंत्रण पर अप्रैल में श्रीलंका दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी

एजेंसी कोलंबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के निमंत्रण पर अप्रैल के पहले सप्ताह में श्रीलंका की यात्रा पर जा सकते हैं। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी। पीएम मोदी की संभावित यात्रा से भारत-श्रीलंका संबंधों में मजबूती आने के साथ ही दोनों पड़ोसी देशों के बीच जन-केंद्रित साझेदारी को गति मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड से वापस आते समय कोलंबो पहुंच सकते हैं। बैंकॉक में 2 से 4 अप्रैल तक बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग व्हल (बिम्स्टेक) शिखर सम्मेलन का छठा आयोजन होगा। दिसानायके ने दिसंबर में तीन दिवसीय भारत यात्रा



करने के लिए आमंत्रित किया था। सितंबर 2024 में पदभार ग्रहण करने के बाद दिसानायके की यह

पहली विदेश यात्रा थी। दोनों नेताओं ने अपनी चर्चाओं के दौरान भारत-श्रीलंका देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने और संबंधों को मैत्रीपूर्ण बनाने पर सहमति

ट्रम्प प्रशासन वेटरन्स अफेयर्स विभाग से 70 हजार से अधिक कर्मचारियों की करेगा छंटनी

एजेंसी वाशिंगटन। अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन वेटरन्स अफेयर्स विभाग (वीए) में 70 हजार से अधिक कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रहा है। वीए चीफ ऑफ स्टाफ क्रिस्टोफर सिरैक ने कहा कि विभाग सरकारी दक्षता विभाग या डीओजीई के साथ साझेदारी में, पूरे विभाग में वीए को पुनर्गठित करने और कार्यबल का आकार बदलने के लिये आक्रामक तरीके से आगे बढ़ेगा। विभाग का लक्ष्य अपने कार्यबल को 2019 के स्तर पर वापस लाना है, जो कि लगभग चार लाख कर्मचारी हैं, जिसका अर्थ है कि 70 हजार से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी के अंत में अरबपति एलन मस्क के नेतृत्व में डीओजीई अपना काम शुरू किया था। उस समय से अब तक देश भर में 30 हजार से ज्यादा संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है। व्हाइट हाउस ने पहले कहा था कि लगभग 75 हजार संघीय कर्मचारियों ने बायआउट



योजना को स्वीकार कर लिया है, जिसके तहत उन्हें 'स्थगित इस्तीफा' देने पर आठ महीने का वेतन दिया जाएगा।इसका अर्थ है कि एक लाख से ज्यादा संघीय कर्मचारियों के पदों में कटौती की गई है, जो 23 लाख संघीय कर्मचारियों का लगभग 4.5 प्रतिशत है। यह व्हाइट हाउस के कर्मचारियों की संख्या को पांच से 10 प्रतिशत कम करने के लक्ष्य के करीब है।

अमेरिका से किसी भी तरह के संघर्ष के लिए तैयार है चीन

चीन के प्रधानमंत्री ली कियॉंग ने घोषणा की कि देश का रक्षा बजट इस वर्ष भी 7.2फीसदी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा, दुनिया में वह परिवर्तन हो रहे हैं जो पिछले सौ वर्षों में नहीं हुए और यह बदलाव तेजी से सामने आ रहे हैं। बीजिंग सरकार देश की अर्थव्यवस्था की स्थिरता बनाए रखने और वैश्विक सहयोगियों को आकर्षित करने की रणनीति पर काम कर रही है। चीन ने खुद को शांति प्रिय और स्थिर राष्ट्र के रूप में पेश करने की कोशिश की है, जबकि अमेरिका को मध्य पूर्व और यूक्रेन में उलझा हुआ देश बताया है।



जापान के कारखाने में विस्फोट से एक व्यक्ति की मौत

एजेंसी टोक्यो। जापान के मध्य प्रांत ऐची में एक कारखाने में धूल संग्राहक यंत्र में विस्फोट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा दो अन्य

के बाद मदद के लिए स्थानीय समानानुसार सुबह करीब 08:०5 बजे आपातकालीन कॉल किया। रिपोर्ट के अनुसार, विस्फोट होने से इमारत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी।



मामूली रूप से घायल हो गए। कयोडो न्यूज ने स्थानीय अग्निशमन अधिकारियों के हवाले से बताया कि टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन की सहयोगी कंपनी चुओ स्पिंग कंपनी के एक कर्मचारी ने विस्फोट

इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा, मामूली रूप से घायल दो और अन्य लोग हैं।

अब ट्रंप ने यूक्रेन के लिए खुफिया जानकारी साझा करने पर भी लगाया प्रतिबंध

एजेंसी वाशिंगटन/कीव। अमेरिका ने यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा करने पर रोक लगा दी है। यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआईए) के प्रमुख ने पुष्टि की है कि अमेरिका ने सैन्य सहायता निर्वाह करने के अलावा यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा करना बंद कर दिया है।सीआईए प्रमुख जॉन रेटक्लिफ का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पास इस बारे में एक वास्तविक सवाल था कि क्या राष्ट्रपति जेलेंस्की शांति प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध हैं? इसी के बाद उन्होंने कहा कि आइए स्कें.. मैं उन्हें (जेलेंस्की को) इस बारे में सोचने का मौका देना चाहता हूं। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज ने कहा कि



सभी पहलुओं की समीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता को निलंबित करने का फैसला लिया था। अब खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान पर प्रतिबंध लगाकर, अमेरिका ने

यूक्रेन को और अधिक मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। यूक्रेन के लिए अमेरिकी खुफिया सहायता बेहद अहम रही है। यह न केवल रूसी सैन्य ठिकानों की पहचान करने बल्कि उनपर हमलों की रणनीति तैयार करने में भी मदद करती थी। रिपोर्ट के अनुसार, तीन अधिकारियों ने पुष्टि की कि वाशिंगटन ने कीव के साथ खुफिया चैनल पूरी तरह से बंद कर दिए हैं।

महंगी पड़ रही लागत, अमेरिका ने अप्रवासियों को भेजने के लिए सैन्य विमानों के इस्तेमाल पर लगाई रोक

एजेंसी कैम्बेरा। अमेरिका ने सैन्य अप्रवासियों को भेजने के लिए सैन्य विमानों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अप्रवासियों को सैन्य विमानों से भेजने की महंगी लागत को देखते हुए यह कदम उठाया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ अप्रवासियों को उनके देश या क्यूबा के त्वांतानामो बे स्थित सैन्य अड्डे तक पहुंचाने के लिए अमेरिकी

सैन्य विमानों का उपयोग महंगा साबित हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि इसलिए आने वाले दिनों कोई उड़ान निर्धारित नहीं की गई है। अंतिम सैन्य निर्वासन उड़ान एक मार्च को हुई थी। उन्होंने कहा कि इस रोक को बढ़ाया जा सकता है या स्थायी किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी और ग्वाटेमाला के अधिकारियों ने जो आंकड़े मुहैया कराए हैं, उसके मुताबिक ग्वाटेमाला के लिए

अमेरिकी सैन्य निर्वासन उड़ान की लागत प्रति अपवासी कम से कम 4675 डॉलर पड़ रही है। यह एक अमेरिकन एयरलाइंस के प्रथम श्रेणी के एकतरफा टिकट की कीमत 853 डॉलर का पांच गुना से अधिक है। साथ ही यह लागत अमेरिकी आबजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) द्वारा संचालित वाणिज्यिक चार्टर उड़ान की लागत से भी काफी अधिक है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से करीब 1.1 करोड़ अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने की बात कही थी। इसके बाद अमेरिकी सेना ने लैटिन अमेरिकी देशों में अवैध अप्रवासियों को लेकर छह उड़ानें भरी हैं। ट्रंप अवैध अप्रवासियों पर शिकंजा कसने के लिए सेना का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने



मेक्सिको सीमा पर सेना के जवानों की तैनाती की है। वहीं अवैध अप्रवासियों को रखने के लिए सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल किया जा रहा है और सेना के विमानों से ही अवैध अप्रवासियों को निर्वासित किया जा रहा है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि सेना के विमानों से अवैध अप्रवासियों को भेजने की लागत नागरिक विमानों की तुलना में बहुत ज्यादा है। अमेरिका ने अब तक कितने

भारतीयों को वापस भेजा अमेरिका अब तक तीन सैन्य विमानों के जरिए 332 भारतीयों को भारत भेजा है। अमेरिका से अवैध प्रवासियों को लाने वाली पहली फ्लाइट 5 फरवरी को भारत के अमृतसर में लैंड हुई। तब इसमें 1०4 लोग सवार थे, जिनमें 30 बंजामी थे। इसके अलावा 15 फरवरी को 116 और 16 फरवरी को 112 भारतीयों को लेकर भी अमेरिकी सैन्य उड़ानें भारत पहुंची थीं।

फ्रेंचबीन (फ्रांसबीन) की खेती

पहाड़ी क्षेत्रों में फ्रेंचबीन (फ्रांसबीन) की बुआई खरीफ में एवं निचले स्थान तथा तराई क्षेत्र में बसन्त ऋतु में की जाती है । यह उत्तर पूर्वी क्षेत्रों एवं महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्रों में रबी में ली जाती है। यह फसल पाला एवं जल भराव के प्रति अधिक संवेदनशील है। फसल की वृद्धि के लिए 10 से 2। डिग्री सेंटीग्रेट अनुकूल तापमान है। 30 डिग्री सेंटीग्रेट से ज्यादा तापमान होने पर फूलों के झड़ने की अधिक समस्या पाई गई है। 5 डिग्री सेंटीग्रेट तापमान से कम होने पर फूलों एवं फलियों तथा शाखाओं में क्षति होती है।

►► **भूमि का चुनाव**

फ्रेंचबीन (फ्रांसबीन) की खेती के लिए गहरे–हल्के गठन वाली बलुई दोमट से बुलाई चिकनी मृदायें उपयुक्त रहती हैं। अधिक जल धारण क्षमता वाली मृदा जिसका पीएचपी मान 6.5 से 1.5 उत्तम रहती है। लवणीय तथा क्षारीय मृदायें अनुपयुक्त रहती हैं। निष्कर्ष यह निकलता है, की फ्रेंचबीन (फ्रांसबीन) की खेती हल्की दोमट मिट्टी से लेकर भारी चिकनी मिट्टी तक में की जा सकती है।

►► **खेत की तैयारी**

प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2 से 3 जुताईयाँ देशी हल या कल्टीवेटर से करने के पश्चात् पाटा चलाकर खेत समतल कर लेना चाहिए। दीमक से फसल सुरक्षा हेतु क्लोरपायरीफास 1.2 प्रतिशत 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिलाना चाहिए और खेत में जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए एवं खेत खरपतवार मुक्त होना चाहिए।

फ्रेंचबीन (फ्रांसबीन) की खेती सब्जी एवं दाना के लिए की जाती है। स्वाद और सेहत के लिहाज से फ्रेंचबीन (फ्रांसबीन) की फलियां (बीन्स) सबसे महत्वपूर्ण होती है, और इसकी जायकेदार सब्जी प्राय: सभी लोग बेहद पसंद करते हैं। अधिक मांग होने की वजह से बाजार में इसकी बीन्स सबसे मंहगे दामों में बिकती है। इसलिए फ्रेंचबीन (फ्रांसबीन) को नकदी फसल के रूप में उगाया जाने लगा है। यह खाने में स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक होता है, और मुनाफे की दृष्टि से अन्य दलहनों से बेहतरीन फसल है।

फ्रेंचबीन (फ्रांसबीन) के दानों में सामान्यत 23 प्रतिशत प्रोटीन, 60 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके 100 ग्राम दानों में 260 मिली ग्राम कैल्शियम, 410 मिली ग्राम फॉस्फोरस, एवं 5.8 मिली ग्राम लौह तत्व पाये जाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते है।

फ्रेंचबीन (फ्रांसबीन) की खेती द्वारा भारत में उत्तर के मैदानी क्षेत्रो, हिमालयन रीजन के पहाड़ी क्षेत्रो और महाराष्ट्र से सबसे अधिक उत्पादन मिलता है। यदि कृषक इसकी खेती वैज्ञानिक तकनीक से करें, तो फ्रेंचबीन (फ्रांसबीन) की फसल से इच्छित उपज प्राप्त की जा सकती है। इस लेख में फ्रेंचबीन (फ्रांसबीन) की उन्नत खेती कैसे करें का विस्तृत उल्लेख है।

वी.एल 60– यह खरीफ एवं रबी दोनों मौसम के लिये उपयुक्त हैं।

इसके दानों का रंग भूरा एवं 100 दानों का वजन 36 ग्राम तक होता है। यह 110 से 115 दिन में पककर 15 से 20 क्किंटल/हेक्टेयर दाना उपज देती है।

अन्य किस्में– बी.एल 63, अम्बर, आई.आई.पी.आर 96–4, उत्कर्ष, आई.आई.पी.आर 98–5, एच.पी.आर 35, बी,एल 63, अरुण और हूर – 15 आदि है।

►► **बोवाई का समय**

फ्रेंचबीन (फ्रांसबीन) की खेती के उत्पादन पर बोवाई के समय का प्रभाव अन्य दलहनी फसलों की अपेक्षा अधिक पड़ता है। देश के उत्तरी पूर्वी भाग में फ्रेंचबीन (फ्रांसबीन) की बोवाई का सबसे उपयुक्त समय अक्टूम्बर के अंतिम सप्ताह से लेकर नवम्बर के प्रथम सप्ताह तक होता है।

पन्तु देश के उत्तर पश्चिमी भाग जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में अधिकतम उपज सितम्बर के मध्य में बोने से प्राप्त होती है। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में जून के अन्तिम सप्ताह से जुलाई के पहले सप्ताह तक बुवाई का उपयुक्त समय है। ढेर से बोवाई करने पर उपज में भारी कमी आ जाती है, क्योंकि ऐसी अवस्था में फ्रेंचबीन (फ्रांसबीन) के पौधों की वानस्पतिक वृद्धि घट जाती है। जिसमे फलियों की संख्या और दानों के भार में काफी कमी आ जाती है।

►► **बीज की मात्रा**

फ्रेंचबीन (फ्रांसबीन) से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए 2.5 से 3.5 लाख पौधे प्रति हेक्टेयर अवश्य होने चाहिए। यह पौध संख्या दानों के भार के अनुसार बीज दर से प्राप्त की जा सकती है।

झाड़ीदार किस्म – 80–90 कि.ग्रा. बीज/हेक्टेयर बेलदार किस्म – 35–30 कि.ग्रा. बीज/हेक्टेयर बीज शोधन

बीजोपचार फफूँदीनाशी रसायन कार्बेन्डाजिम (बाविस्टीन 50 डब्ल्यूी) 3 ग्राम प्रति किलो ग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करना आवश्यक है, या 2 से 3 ग्राम थीरम से प्रति किलोग्राम बीज की मात्र के हिसाब से बीज शोधन करना चाहिए।

►► **बुवाई विधि**

फ्रेंचबीन (फ्रांसबीन) की खेती के लिए लाइन से लाइन की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखते है, और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते है, इसकी बुवाई 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर करते है। लेकिन बेलदार किस्मों के लिए पंक्ति से पंक्ति 100 से.मी. की दूरी रखनी चाहिए तथा पौधों को सहारा देने का प्रबंध आवश्यक है। बीज अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी का होना भी आवश्यक है।

►► **खाद एवं उर्वरक**

फ्रेंचबीन (फ्रांसबीन) की अधिक उपज लेने के लिए खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करना आवश्यक है। गोबर की खाद या कम्पोस्ट 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की अंतिम जुताई के समय मिलाना चाहिए। इसके साथ साथ 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 30 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर तत्व के रूप में देना आवश्यक है।

नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस एवं पोटाश की

उन्नत किस्में

झाड़ीदार किस्में – जाईंट स्ट्रिंगलेस, कंटेंडर, पेसा पार्वती, अका कोमल, पंत अनुपमा तथा प्रीमियर, वी.एल. बोनी–1 बेलदार किस्में – कंटुकी वंडर, पूसा हिमलता व एक.वी0एन.– 1

एच.यू.आर15– सफेद दानों वाली किस्म है। इसके 100 दानों का वजन 40 ग्राम तक है, तथा 120 से 125 दिनों में पककर तैयार होती है। इसकी उपज 18 से 22 क्किंटल प्रति हेक्टेयर है।

पी.डी.आर 14 (उदय)– यह बड़े दानों वाली किस्म है, जिसके 100 दानों का वजन 44 ग्राम तक होता है, तथा इसके दानों का रंग सफेद–चितीदार होता है। यह किस्म 125 से 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, तथा इसकी अधिकतम उत्पादन क्षमता 20 से 25 क्किंटल प्रति हेक्टेयर हैं।

एच.यू.आर 15– सफेद दानों वाली किस्म है। इसके 100 दानों का वजन 40 ग्राम तक है, तथा 120 से 125 दिनों में पककर तैयार होती है। इसकी उपज 18 से 22 क्किंटल प्रति हेक्टेयर है।

पूरी मात्रा बुवाई के समय तथा बची आधी नत्रजन की आधी मात्रा खड़ी फसल में देनी चाहिए। इसके साथ ही 20 किलोग्राम गंधक की मात्रा देने से लाभ होता है। 20 प्रतिशत यूरिया के घोल का छिड़काव बुवाई के बाद 30 दिन तथा 50 दिन में करने पर उपज अच्छी मिलती है।

►► **रोग एवं रोकथाम**

एन्टेक्नोज– फ्रेंचबीन (फ्रांसबीन) के प्रभावित पौधे के बीजपत्र पर पीले–भूरे चित्तेदार धब्बे दिखाई देते हैं। पत्तियों के ऊपरी, निचली एवं साथ ही साथ तनों पर भी गहरे रंग के धारीदार धब्बे दिखाई देते हैं।

►► **रोकथाम–**

1. बीजोपचार थायरम + कार्बेन्डाजिम (2:1) 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज ग्राम की दर से उपचार करें।
2. मैकोजेब का छिड़काव 0.25 प्रतिशत (2.5 ग्राम प्रति लीटर) दर से अथवा कार्बेन्डाजिम 0.1 प्रतिशत (1 ग्राम प्रति लीटर) का 2 से 3 बार पत्तों पर छिड़काव बुवाई के 40, 60 एवं 75 दिन के बाद करें।
3. संक्रमित पौधे को खेत से बाहर निकाले तथा फसल अवशेष को नष्ट करें।
4. 2 से 3 साल का फसलचक्र अपनारें।
5. फव्वारा पद्धति से सिंचाई न करें।

6. खेत में अधिक नमी होने पर आवाजाही न करें।
तना गलन– इसके प्रारम्भिक लक्षण फ्रेंचबीन (फ्रांसबीन) की पत्तियों पर छोटे जलीय धब्बे के रूप में संक्रमण के 4 से 10 दिन में ही दिखाई देने लगते हैं। धब्बों का केन्द्र सूख कर भूरा तथा किनारे चमकोले पीले रंग के हो जाते रोकथाम–

1. कार्बेन्डाजिम का 0.1 प्रतिशत (1 ग्राम प्रति लीटर) की दर से 2 से 3 बार पत्तियों पर छिड़काव फूल आने के समय एवं उसके पहले करें।
2. जल्दी अथवा समय पर बुवाई करें।
3. अच्छी जल निकासी वाली भूमि में बुवाई करें।
4. घनी बुवाई ना करें।
कोणीय धब्बे– फ्रेंचबीन (फ्रांसबीन) की पत्तियों पर कोणीय लाल भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। धब्बे आपस में मिलकर नेकोसिस जैसी अवस्था बनाकर पत्तियों को गला देती है।

रोकथाम–

1. बीजोपचार फफूँदनाशक दवा कार्बेन्डाजिम से 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करें।
2. कार्बेन्डाजिम का छिड़काव (0.1 प्रतिशत) संक्रमण की शुरुआत में तथा बुवाई के 5 से 6 सप्ताह पश्चात पर्ण छिड़काव के रूप में करें।
3. कटाई पश्चात् गहरी जुताई कर फसल अवशेष नष्ट करें।

►► **कीट एवं रोकथाम**

पर्ण सुरंगक– फ्रेंचबीन (फ्रांसबीन) की पत्तियाँ पीली हो कर झड़ जाती हैं। अधिक संक्रमित पौध बौने रह जाते हैं। यह कीट वनस्पतीय अवस्था में दिखाई देते हैं।

रोकथाम–

1. मिथाइल डेमेटॉन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
2. संक्रमित पौधों को निकालकर खेत से दूर नष्ट करें।
3. संक्रमित पत्तियों को तोड़कर नष्ट करें।
4. नीम के पानी का छिड़काव भी पर्ण सुरंगक के लिए लाभप्रद है।

तना मक्खी– तनों का फूल जाना एवं दो हिस्सों में टूटना अथवा पाश्र्व जड़ों का न बनना, संक्रमित पौधे में आकस्मिक जड़ों का दिखाई देना। अंकुरित पौधों का सूख कर मर जाना।

रोकथाम–

1. क्लोरोपायरीफॉस 8 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम की दर से बीजोपचार करें।
2. फोरेट 10 जी 10 किलोग्राम मात्रा का बुवाई के समय उपयोग करें।
3. पलवार की मदद से मुदा में नमी बरकरार रखना जिससे आकस्मिक मेगट क्षति से बचा जा सके।
काला माहू– यह कीट पत्तियों के रस को चूसता है। अधिक संक्रमित पौधों की पत्तियाँ सूख कर मुड़ जाती हैं। फलियां बौनी एवं विकृत हो जाती हैं। पौधे सूख कर मर जाते हैं।

रोकथाम–



1. जैविक नियंत्रण काकसिनेला सेप्टमपंकटा 1000 वयस्क प्रति 400 वर्ग मीटर के हिसाब छोड़ें।
2. इमिडाक्लोरोप्रिड 11.8 एस एल की 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
3. सिस्टेमिक कीटनाशक जैसे डायमिथिएट या मिथाइल डेमेटान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से छिड़काव करें।
हरी सब्जी की तुड़ाई फूल आने के 2–3 सप्ताह बाद आरंभ हो जाती है। तुड़ाई नियमित रूप से जब फलियाँ नर्म व कच्ची अवस्था में हों, तभी करें। 120 से 130 दिन में फसल पक कर तैयार हो जाती है। कटाई के बाद 3 से 4 दिन तक फसल को धूप में सुखाएं, जब तक बीज की नमी 9 से 10 प्रतिशत न हो जाए। उसके बाद दानों को भूसे से अलग कर लें।

►► **पैदावार**

उपरोक्त वैज्ञानिक विधि से फ्रेंचबीन (फ्रांसबीन) की खेती करने और फसल के अनुकूल परिस्थितियों में हरी फली उपज 15–100 क्किंटल/हेक्टेयर की दर से प्राप्त होती है। यह प्रजाति के प्रकार पर भी निर्भर करती है। दाना के लिए 20 से 30 क्किंटल प्रति हेक्टेयर सिंचित खेती से मैदानी क्षेत्रों में तथा । से 12 क्किंटल प्रति हेक्टेयर बारानी में उपज प्राप्त होती है।

अधिक उत्पादन लेने हेतु आवश्यक बिंदू–
1. ग्रीष्म कालीन गहरी जुताई तीन वर्ष में एक बार अवश्य करें।
2. बुवाई पूर्व फ्रेंचबीन (फ्रांसबीन) का बीजोपचार अवश्य करें।
3. पोषक तत्वों की मात्रा मृदा परीक्षण के आधार पर ही दें।
4. पौध संरक्षण के लिये एकीकृत पौध संरक्षण के उपायों को अपनाना चाहिए।
5. खरपतवार नियंत्रण अवश्य करें।

फ्रांसबीन की सब्जी

फ्रेंचबीन (फ्रांसबीन) की हरी पौध सब्जी के रूप में खायी जाती है तथा सुखा कर इसे राजमा, लोबिया इत्यादि के रूप में खाया जाता है। हरी बीन्स या सामान्य भाषा में फ्रेंच बीन्स में मुख्यतः पानी, प्रोटीन, कुछ मात्रा में वसा तथा कैल्सियम, फास्फोरस, आयर्न, कैरोटीन, थायमीन, राइबोफलेविन, नियासीन, विटामिन सी आदि तरह के मिनरल और विटामिन सौत होते हैं। बीन्स विटामिन बी2 का मुख्य स्रोत होते हैं। बीन्स सोल्युबल फाइबर का अच्छा स्रोत होते हैं और इस कारण हृदय रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ऐसा माना जाता है कि एक कप पका हुआ बीन्स रोज़ खाने से रक्त में कोलेस्टेरोल की मात्रा 6 हफ्ते में 10 प्रतिशत कम हो सकती है और इससे हृदयाघात का खतरा भी 40 प्रतिशत तक कम हो सकता है। बीन्स में सोडियम की मात्रा कम तथा पोटेशियम, कैल्सियम व मेग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है और लवणों का इस प्रकार का समन्वय सेहत के लिए लाभदायक है। इससे रक्तचाप नहीं बढ़ता तथा हृदयाघात का खतरा टल सकता है।



मिश्रित खेती



आजकल के युग में खेती योग्य भूमि पर जनसंख्या का बोझ दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में मिश्रित खेती अपना कर किसान प्रति इकाई भूमि से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। हमारे देश में कृषिगत क्षेत्र का लगभग 65 प्रतिशत भाग वर्षा पर आधारित है।

प्राकृतिक आपदा जैसे अनावृष्टि के कारण–सूखा या अतिवृष्टि के कारण बाढ़ के फलस्वरूप बहुधा फसलें बिलकुल नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार की परिस्थिति में आर्थिक दृष्टिकोण से मिश्रित खेती सुरक्षा कवच का काम करती है।

जब एक बार में एक से अधिक फसल एक जगह पर उगाया जाती है तो उसे मिश्रित फसल कहते हैं। पुराने समय से ही मिश्रित फसलों की खेती हमारी कृषि प्रणाली का एक अभिन्न अंग रही है। हमारे पूर्वजों ने बहुफसलीय खेती की संकल्पना मौसम की विपरीत परिस्थितियों में फसल सुरक्षा के लिए की थी।

क्योंकि जब एक खेत में एक ही साथ दो–या–दो से अधिक फसलें उगाई जाती हैं तो यह संभावना होती है कि अगर कोई फसल मौसम की असामान्यता के कारण नष्ट हो जाए तब भी दूसरी या तीसरी फसल बच सकती है। ऐसे में उस विषम परिस्थिति में भी खेत से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सिन्धु घाटी की सभ्यता के एक प्रमुख स्थल कालीबंगा से मिले जुताई के कूड़ों से पता चला है कि उस समय भी कई फसलों को एक साथ मिला कर खेती की जाती थी। मोहनजोदड़ो में गेहूँ, जौ तथा चना की खेती एक साथ मिला कर की जाती थी।

सभी फसलों की वृद्धि का क्रम, उनकी जड़ों की गहराई और उनके पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग–अलग होती है।

ऐसे में दो ऐसी फसलें जैसे आलू + मक्का, हल्दी + अरहर, मूंगफली + अरहर, जिनमें एक उथली जड़ वाली और दूसरी गहरी जड़ वाली हों, तो दोनों मिट्टी की अलग–अलग सतहों से नमी एवं पोषक तत्वों का भरपूर अवशोषण तथा उपयोग करती हैं और इस प्रकार जल एवं पोषक तत्वों के उपयोग की क्षमता बढ़ने से उनकी उपज बढ़ जाती है।

वहीं कुछ फसलों की उपस्थिति उसकी सहयोगी फसल को कोड़ों के आक्रमण से बचाती है। जैसे मक्का की फसल में ज्वार, लाल मिर्च में सौंफ तथा चना की फसल में धनिया की मिश्रित खेती कुछ ऐसे ही उपयोगी उदाहरण हैं।

सिंचित क्षेत्र के लिए मिश्रित फसल प्रणाली

रबी मक्का + आलू, आलू + बाकला, रबी मक्का + राजमा (मैदानी क्षेत्रों के लिए)
रबी मक्का + धनिया (हरी पत्तियों के लिए), शरदकालीन गन्ना+ मिर्च, गन्ना + धनिया, गन्ना+ममरैला, गन्ना+लहसुन, गन्ना+ आलू, गन्ना+गेहूँ, गन्ना+अजवाइन, गन्ना+मसूर, बसन्त कालीन गन्ना+भिण्डी, गन्ना+मूंग ?
गन्ना+उड़द, प्याज+अजवाइन, प्याज+भिण्डी, प्याज+मिर्च, सौंफ+मिर्च
असिंचित क्षेत्र के लिए मिश्रित फसल प्रणाली
बाजरा+ मूंग, बाजरा+अरहर, मक्का+उड़द, गेहूँ+चना, जौ+चना, जौ + मटर, ज्वार+ अरहर और गेहूँ+मटर

अनाज के फसलों का तिलहन फसलों के साथ मिश्रण

गेहूँ+सरसों, जौ+ सरसों, गेहूँ+अलसी, जौ+अलसी

दलहन फसलों का दलहन और तिलहन फसलों के साथ मिश्रण

अरहर+मूंग, अरहर+उड़द, अरहर+मूंगफली, चना+ अलसी, चना + सरसों, मटर+सरसों, मटर+कुसुम

दो से अधिक फसलों का मिश्रण

ज्वार+अरहर+मूंग , बाजरा+अरहर+मूंग, ज्वार+अरहर+उड़द, जौ+मटर+ सरसों, चना+ सरसों+अलसी, चना+अलसी+कुसुम और गेहूँ+चना+सरसों

आइए यहां हम आपको कुछ फसलों के साथ मिश्रित फसल खेती की पूरी प्रक्रिया की जानकारी विस्तृत रुप से देते हैं।

सबसे पहले जून महीने के तीसरे–चौथे सप्ताह तक खेत में पड़ा कूड़ा–करकट साफ कर देते हैं। उसके बाद बारिश होने के बाद खेत की पहली जुताई ट्रैक्टर से कराते हैं। फिर दो से तीन जुताई हल से और ट्रैक्टर से करते हैं।

ऐसी फसल बोने को प्राथमिकता देते हैं, जिनमें पानी की आवश्यकता कम हो। साथ ही एक फसल चक्र पूरा होने के बाद दूसरे फसल चक्र में अलग फसलों की बुवाई करते हैं। प्रतिवर्ष फसल बदल–बदल कर बोते हैं, जिससे खेत को पर्याप्त पोषक तत्व व नमी मिलती रहे।

घर पर संरक्षित व सुरक्षित देशी बीजों का प्रयोग करते हैं।

बीज की मात्रा

एक एकड़ खेत में मिश्रित बुवाई करने के लिए अरहर 5 किलोग्राम, बाजरा 2 किलोग्राम, मूंग 2 किलोग्राम और तिल डेढ़ किलोग्राम को मिलाकर बुवाई करते हैं।

बुआई का समय और तरीका

अगस्त महीने के पहले हफ्ते में छिटकवा विधि से बुवाई करते हैं। इसके लिए खेत की आखिरी जुताई ट्रैक्टर से करने के पश्चात् 3 से 5 इंच की गहराई पर इसकी बुवाई ट्रैक्टर की सहायता से सोड्राइल मशीन से ही कराते हैं।

एक एकड़ हेतु एक ट्राली देशी खाद की आवश्यकता होती है, जिसे पहली जुताई के समय खेत में मिला दिया जाता है। किसान चाहे तो जीवामृत का भी प्रयोग कर सकते हैं।

फसल की बढवार होती रहे, इसके लिए समय–समय पर खेत की निराई की जाती है। इससे एक तरफ तो हमारा खेत साफ रहता है और दूसरी तरफ जानवरों के लिए चारा भी उपलब्ध हो जाता है।

बाजरा, मूंग व तिल के पकने की अवधि 60–90 दिनों की होती है, जबकि अरहर 8–9 महीने की फसल ही है, जो मार्च में पक जाती है।

तिल की फसल की कटाई सितम्बर के अंतिम सप्ताह या फिर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक हो जाती है। तिल की कटाई करके, एक जगह सुखा कर, डण्टल को हिलाकर इसका बीज झाड़ लिया जाता है।

मूंग की एक–एक फली की तुड़ाई की जाती है। यह तुड़ाई सितम्बर के प्रथम सप्ताह से प्रारम्भ हो जाती है। इसकी कुटाई करके बीज निकाला जाता है।

बाजरा की कटाई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवम्बर के प्रथम सप्ताह तक हो जाती है। बाजरा की मड़ाई बैलों से करते हैं। इसके दाने निकालने के लिए श्रेसर का प्रयोग भी किया जा सकता है। मार्च में अरहर पकने के बाद इसकी कटाई कर लेते हैं। अरहर को काटकर सुखाते हैं। तब कुटाई करके इसका बीज निकालते हैं।

देशी बाजरा – 4 क्किंटल

देशी अरहर – 1 क्किंटल

देशी तिल– 50 किलोग्राम

देशी मूंग– 30 किलोग्राम

मिश्रित फसल उत्पादन से लाभ

इससे भूमि की बचत होती है।

खेत की लागत कम हो जाती है।

मैसेज फसलोत्पादन फसलों के असफलता के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा है अथवा इंश्योरेंस।

भूमि से जल तथा पोषक तत्वों के अवशोषण में संतुलन बना रहता है।

प्रति इकाई खेत से अधिक उपज पैदा होती है।

मृदा का कटाव कम हो जाता है।